लखनऊ

रविवार, 21 जून, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 295

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

भगवान ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं। या तो देकर जाइए या फिर छोड़कर जाइए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए सदा प्रसन्न रहें।

TODAY WEATHER

DAY 41° Hi | NIGHT 29° Low

ओडिशा को 47,600 करोड़ की सौगात: पीएम मोदी बोले- कांग्रेस राज में पिछड़ा रहा पूर्वी भारत, अब बना विकास का गेटवे

मयूरभंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पूर्वी भारत हमेशा पिछड़ा रहा। लेकिन आज यही क्षेत्र देश के विकास का मुख्य द्वार बन रहा है। पीएम मोदी ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ओडिशा के लिए 47,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ओडिशा अब विकास की राह पर तेजी से दौड़ रहा है। कल्याणकारी योजनाएं गरीबों का जीवन बदल रही हैं।

डबल इंजन सरकार की डबल विशेषता: प्रधानमंत्री

पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा इस समय उत्सव के माहौल में डूबा हुआ है। पिछले हफ्ते यहां गण पर्व (राजा पर्व) मनाया गया। अब महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और बारीपदा रथ यात्रा की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही हैं। लोकतंत्र और विकास का यह उत्सव अद्भुत है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि डबल इंजन सरकार की डबल विशेषता ये है कि वो खुद जनता तक पहुंचती है। हमारा प्रयास है कि सामान्य नागरिक को किसी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।

विकास का नया गेटवे बना पूर्वी भारत

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार 'पूर्वोदय' नीति पर काम कर रही है। हमारा लक्ष्य पूर्वी भारत के विकास से पूरे देश का विकास करना है। जो पूर्वी भारत कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन की पहचान बन चुका था, वह अब प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है। भाजपा सरकार ओडिशा के संसाधनों को नई संभावनाओं में बदल रही है। राज्य को अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। ओडिशा में भाजपा सरकार को दो साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर पीएम ने राज्य की जनता को बधाई दी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गांव पहुंचे प्रधानमंत्री

पीएम मोदी के लिए यह दिन बेहद खास रहा। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन भी था। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ओडिशा की बेटी आज देश के सर्वोच्च पद पर है। वह हम सभी का मार्गदर्शन कर रही हैं। यह पूरे देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने मयूरभंज और ओडिशा की पहचान को पूरे विश्व में मजबूत किया है। पीएम मोदी राष्ट्रपति के ससुराल पहाड़पुर गांव भी गए। वहां उन्होंने स्थानीय बच्चों के स्कूल का दौरा किया। पीएम ने बच्चों के साथ कुछ यादगार पल बिताए। उन्होंने इसे अपने लिए एक शैक्षणिक और कुछ नया सीखने वाला अनुभव बताया।

पीएम-जनमन अभियान राष्ट्रपति के मार्गदर्शन का ही परिणाम: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'पीएम-जनमन अभियान राष्ट्रपति के साथ हुई चर्चाओं और उनके मार्गदर्शन का ही परिणाम है। ये ऐसे जन जातीय समूहों के लिए है जो जन जातीय समुदायों में भी सबसे पीछे रह गए हैं। सरकार अब स्वयं चलकर ऐसे जन जातीय समुदायों के घर तक पहुंच रही है। आदिवासी युवाओं को हम शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ रहे हैं। देश में करीब 500 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए हैं।'

47,600 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात

ओडिशा के विकास सफर को रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी ने बड़ी घोषणाएं कीं। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की नींव रखी गई। सरकार का पूरा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीब कल्याण पर है। इन परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ओडिशा की तस्वीर तेजी से बदल रही है।

संक्षेप

टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में फाल्टा पुलिस स्टेशन पर हमले और TMC नेता जहांगीर खान को छुड़ाने की साजिश के सिलसिले में उसकी पत्नी रेजिना बीबी को गिरफ्तार किया। वह तीन दिन से फरार थीं। पुलिस के मुताबिक, रेजिना ने ही इस हमले की योजना बनाई थी। बताया जा रहा है कि रेजिना बीबी पिछले करीब तीन दिनों से फरार चल रही थी। उन पर फाल्टा पुलिस स्टेशन पर हमले की कोशिश के पीछे मास्टरमाइंड होने का आरोप है। कई आपराधिक मामलों में आरोपी खान को नेपाल सीमा के पास से पकड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद से फरार रेजिना बीबी को एक सूचना के आधार पर दक्षिण 24 परगना जिले के जुलपिया इलाके से पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार, रेजिना ने समर्थकों को जुटाने और उस प्रदर्शन की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका कथित उद्देश्य फाल्टा में दोबारा हुए चुनाव में तृणमूल के उम्मीदवार जहांगीर खान को छुड़ाना था। कई आपराधिक मामलों में आरोपी खान को नेपाल सीमा के पास से पकड़ा गया था। वहीं, इस मामले में रेजिना बीबी की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 26 हो गई है। पुलिस का कहना है कि लोगों को इकट्ठा करने और उसके बाद पुलिस स्टेशन पर हुए हमले के पीछे रेजिना साजिशकर्ताओं में से एक थीं। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि हिंसा से एक दिन पहले रेजिना की अगुवाई में एक बैठक हुई थी, जिसमें पुलिस स्टेशन से लगभग तीन किलोमीटर दूर समर्थकों को इकट्ठा करने और फिर एक व्यवस्थित तरीके से वहां तक मार्च करने की योजना बनाई गई थी।

अपराध करने वाले में डर होना चाहिए... राजेंद्र सैनी हत्याकांड में दो दोषियों को फांसी की सजा

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की अदालत ने आठ साल पुराने चर्चित राजेंद्र सैनी हत्याकांड में आज बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने इस हत्याकांड में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अपराध करने वाले व्यक्ति को डर होना चाहिए। ये मामला साल 2018 का है, जहां मीरापुर थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव के जंगल में एक युवक का जला हुआ शव बरामद हुआ था। इसके बाद में उसकी पहचान ककरौली निवासी 26 साल के राजेंद्र सैनी के रूप में हुई। पुलिस जांच में ये सामने आया कि अवैध संबंधों के शक में राजेंद्र की हत्या की गई थी। जानकारी के मुताबिक, आरोपी चार जून 2018 को राजेंद्र सैनी नाम के एक युवक को बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए थे। इसके बाद राजेन्द्र को पहले शराब पिलाई और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को छिपाने के लिए अभियुक्तों ने राजेन्द्र के शव को जंगल में ले जाकर जला दिया था। उस दौरान जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में वीरसैन, गजेंद्र उर्फ गीलू और राम किरण उर्फ सावन के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल के दौरान मुख्य आरोपी वीरसैन की जहां मृत्यु हो गई थी तो वहीं दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा न्यायालय में जारी रहा था।

परीक्षा घोटालों के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, जवाबदेही की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर जुटी भीड़

नई दिल्ली, एजेंसी। कथित परीक्षा अनियमितताओं, बार-बार होने वाले पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर युवा नेतृत्व वाले संगठन कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना दूसरा बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक शामिल हुए। प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। छात्र हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा से जुड़े सवालों के जवाब मांग रहे थे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और परीक्षा प्रबंधन में कथित खामियों के खिलाफ आवाज उठाई। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन में शामिल होने वालों से 'थाली और चम्मच' लेकर आने की अपील की थी। उनके आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग थालियां और चम्मच लेकर पहुंचे और उन्हें बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस प्रदर्शन से पहले अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र भी लिखा था। इस पत्र में उन्होंने छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की थी। वहीं, सीजेपी लगातार परीक्षा संबंधी मामलों के प्रबंधन को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी कर रही है। 20 जून को हुआ यह प्रदर्शन जंतर-मंतर पर सीजेपी के पहले आंदोलन के बाद आयोजित किया गया।

भाजपा नेताओं की शॉपिंग में बिजी... खरगे का निशाना, कहा- लोगों लिए जरूरी चीजें खरीदना महंगा

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने "तेजी से घटती बचत और महंगाई" के मामले में सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी दूसरी पार्टियों से नेताओं को "खरीदने" में व्यस्त है, जबकि आम आदमी के लिए जरूरी चीजें खरीदना भी मुश्किल हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के "अर्थव्यवस्था के खराब प्रबंधन" के बोझ तले आम परिवार बर्बाद हो रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खरगे ने कहा कि महंगाई के कारण बचत तेजी से घट रही है। चीजें महंगी हो गई हैं, उम्मीदें टूटी हैं, असमानता बढ़ी है, दुनिया में साख गिरी है और युवाओं में भारी गुस्सा है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "मोदी सरकार के अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के बोझ तले परिवार बर्बाद हो रहे हैं।"

खरगे ने कहा, "खुदरा महंगाई 16 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है। खाने-पीने की चीजों की महंगाई 4.78% है, थाली से टमाटर गायब हैं। मेडिकल महंगाई 15% से ज्यादा है। रुपया तेजी से गिर रहा है। विदेशी निवेशक हमसे दूर हो रहे हैं। युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है।"

'महंगाई के ट्रेंड पर नजर रखनी होगी'

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चेतावनी दी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) को महंगाई के ट्रेंड पर नजर रखनी होगी, खासकर मई में ईंधन की कीमतों में बदलाव को देखते हुए। उन्होंने कहा, "हमें महंगाई के ट्रेंड पर नजर रखने की जरूरत है। आगे चलकर, मई में पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों में बदलाव से आने वाले महीनों में फ्यूल से जुड़ी महंगाई बढ़ सकती है।" US-ईरान युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी से तेल की सप्लाई में रुकावट और लगातार तनाव के बीच, केंद्र सरकार ने एक महीने में तीन बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाईं।

अगर आपके बच्चे भी खाते हैं किंडर जॉय-पनीर समेत ये 12 चीज तो हो जाएं अलर्ट, फस्सई ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसी। अगर आप भी बाजार में बिकने वाले पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर लिखे 'नो एडेड शुगर', '100% नेचुरल' या 'हार्ट प्रो' जैसे लुभावने दावों पर भरोसा करते हैं, तो सावधान हो जाइए। देश की शीर्ष खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बाजार में सक्रिय एक दर्जन से अधिक नामी फूड ब्रांड्स के दावों को भ्रामक और वैज्ञानिक कसौटी पर फेल पाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नियामक का साफ आरोप है कि कंपनियां अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए पैकेट पर ऐसे दावे कर रही हैं, जिनका न तो कोई वैज्ञानिक आधार है और न ही वे उत्पाद के भीतर मौजूद वास्तविक सामग्री से मेल खाते हैं। नियामक की जांच के दायरे में प्लक, बेला, मास्टरचाउ, सफोला, फेरेरो (किंडर जॉय) और ओरविल माउंटेन बावर्ची जैसे नामी गिरामी ब्रांड्स आए हैं। इसके अलावा इनक्रिपो गोल्ड पाउडर वेनिला, कोरियन जिनसेंग सप्लीमेंट, बुरांश स्क्वॉश, नेक्सा इंडस्ट्रीज के अल्कलाइन न्यूट्रिएंट वॉटर और रॉ प्रेसरी के अल्फांसो मैंगो फ्रूट ड्रिंक को लेकर भी सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। FSSAI ने सभी संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी है। नो एडेड शुगर के नाम पर गन्ने का रसः 'प्लकर' के मैंगो फ्रूट जूस पर बड़े अक्षरों में 'नो एडेड शुगर' का दावा किया गया था। लेकिन जब इसकी सामग्री सूची की जांच की गई, तो उसमें 51 फीसदी आम का गूदा और 49 फीसदी गन्ने का रस पाया गया।

नीट छात्र को अबू धाबी सेंटर, भड़के राहुल गांधी बोले- बच्चों के भविष्य से जुएबाज़ी बंद करो

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार और देश की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की। यह आलोचना तब की गई जब नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा देने वाले एक छात्र को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अपना एडमिट कार्ड देखने के बाद छात्र बहुत तनाव में आ गया, क्योंकि उसके पास विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट भी नहीं था। उन्होंने कहा कि नागपुर का एक छात्र एक महीने से नीटकी दोबारा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। उसका सेंटर अबू धाबी में निकला। न पासपोर्ट, न परिवार के पास उसे विदेश भेजने के लिए पैसे, और अब समय भी नहीं बचा था। वह पूरी रात रोता रहा और परीक्षा देने से इनकार कर रहा है - यह किस तरह का तनाव है, क्या आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? गांधी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि परीक्षा में शामिल होने वाले किसी भी छात्र को अपने सेंटर तक न पहुँच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? कल किसी भी छात्र को अपने सेंटर तक न पहुँच पाने को लेकर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए थी। NTA असल में देश के बच्चों और उनके माता-पिता के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, ₹जो सिस्टम किसी बच्चे को उसके अपने शहर में परीक्षा केंद्र नहीं दे सकता, बल्कि उसे विदेश भेज सकता है, उसे परीक्षा आयोजित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश का शिक्षा सिस्टम पूरी पीढ़ी के पैसे और समय की वसूली का ज़रिया बन गया है।

कुर्सी की खातिर तोड़ी जा रहीं पार्टियां... शिवसेना में टूट की आहट के बीच उद्धव को राज ठाकरे का समर्थन

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को शिवसेना (UBT) के 6 लोकसभा सांसदों की बगावत के बीच अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक फायदे के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों को बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुंबई में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "यहां सांसदों को बांटने की कोशिशें चल रही हैं, सत्ता के लिए राजनीति जोरों पर है। मेरा मानना है कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं से ज्यादा आम लोगों को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक पुरानी कहावत है: 'जब आत्म सम्मान खत्म हो जाता है, तो सिर्फ जिंदा लाशें बचती हैं।" राज ठाकरे ने आगे कहा कि सत्ता पाने की दौड़ में, राजनीतिक पार्टियां महाराष्ट्र और देश के सामने मौजूद बड़े मुद्दों को भूल रही हैं। उन्होंने कहा, "विधायकों और सांसदों को किडनैप करने के इस खेल में, हम अपनी मूल बातें भूल रहे हैं। हम महाराष्ट्र की परंपरा, महाराष्ट्र का इतिहास, देश की परंपरा भूल रहे हैं।" उनका यह बयान उद्धव ठाकरे के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने शिवसेना (UBT) के अंदर बगावत पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा था कि चुनौतियों के बावजूद वह पक्के इरादे वाले हैं और अगर कार्यकर्ताओं का उन पर से भरोसा उठ गया तो वह पार्टी प्रमुख का पद छोड़ने को तैयार हैं। शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम में उद्धव ने कहा, "मुझे खुशी होगी अगर पार्टी के किसी लीडरशिप लीडर को अगला शिवसेना प्रेसिडेंट बनाया जाए।

यह कोई धर्मशाला नहीं, इस देश में वही रहेगा जो यहां जन्मा है... घुसपैठियों को अमित शाह की चेतावनी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर में सभा को संबोधित करते उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर निशाना साधा और इसके साथ ही कहा कि एक-एक घुसपैठियों को देश से बाहर करेंगे। यह देश कोई धर्मशाला नहीं है, यहां वही रहेगा, जो यहां जन्मा है। अमित शाह ने कहा कि मैं आज विश्वास के साथ कोल्हापुर की धरती से कह कर जाता हू। बंगाल की जनता ने आशीर्वाद दिया है। विश्वास दिलाता हूं कि न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी।

अमित शाह ने कहा कि देश भर से एक-एक घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकलेंगे। उद्धव जी कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। घुसपैठियों को वोटबैंक बनाकर जीना चाहते हैं। कान खोलकर सुन लो, यह कोई धर्मशाला नहीं है, यहां वही रहेगा, जो इस देश में जन्मा है। भारत की सुरक्षा की सुनिश्चितता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की जाएगी।

पीएम मोदी ने बनाया रिकॉर्ड

अमित शाह ने कहा कि अभी-अभी पीएम मोदी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। देश में सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। इन 12 वर्षों के दौरान मोदी जी के नेतृत्व में सोमनाथ से लेकर गंगासागर तक और पूरे देश में,भारतीय जनता पार्टी तथा NDA का शासन फैलाने का कार्य हुआ है।

उन्होंने कहा कि लोग कहा करते थे कि आप देश के हर हिस्से तक पहुंच जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल का क्या होगा? किंतु पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद और समर्थन प्रदान किया है।

पूरे देश में हो रहा सांस्कृतिक पुनर्जागरण

अमित शाह ने कहा कि हम सब बहुत छोटे थे, राम जन्मभूमि के आंदोलन में नगर में निकलते थे, कई अनुभवी नागरिक कहते थे कि हमारे और आपके जीवन में मंदिर नहीं बनेगा। हमें भी कई बार लगता था कि जीते जी मंदिर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे।

टीएमसी में 440 करोड़ का 'फंड वॉर', तीन बैंक अकाउंट फ्रीज ; बागी विधायकों की शिकायत से सियासी भूचाल

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसदों और विधायकों की बगावत और अब पार्टी के खातों में जमा पैसों को फ्रीज कर दिया गया है। दरअसल, पार्टी के बागी विधायकों की शिकायत के बाद पार्टी के तीन बैंक खातों, जिनमें लगभग 440 करोड़ जमा हैं, के डेबिट ऑपरेशन को फ्रीज कर दिया गया है। बता दें कि पार्टी के बागी विधायकों ने इन फंड्स के स्रोत की जांच की मांग की थी। इससे विपक्षी पार्टी के वित्तीय फंड पर नियंत्रण को लेकर चल रही अंदरूनी लड़ाई और तेज हो गई है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने PTI को बताया कि निजी क्षेत्र के एक बैंक में मौजूद इन तीन खातों को 'डेबिट फ्रीज़' के दायरे में रखा गया है, जिससे पैसे निकालने या बाहर ट्रांजैक्शन करने पर रोक लग गई है, हालांकि पैसे जमा (क्रेडिट) होते रहेंगे। यह घटनाक्रम टीएमसी के अंदर सत्ता के लिए चल रही उस लड़ाई के बीच हुआ है, जो हालिया विधानसभा चुनावों में हार के बाद पार्टी के संगठनात्मक और वित्तीय कामकाज पर नियंत्रण को लेकर पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास और विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के गुटों के बीच तेज हो गई है। यह फ्रीजिंग बनर्जी से जुड़े 10 विधायकों की शिकायतों के बाद हुई है। उन्होंने बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के तहत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराकर FIR दर्ज करने और खातों की विस्तृत जांच की मांग की थी।

राजभर का अखिलेश पर हमला जारी, बोले- उनको अयोध्या के राम मंदिर के बारे में कोई जानकारी नहीं

आर्यावर्त संवाददाता

अंबेडकरनगर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के चढ़ावे में चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लगातार बयान देने के प्रकरण पर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। एक्स पर अखिलेश यादव की पोस्ट पर सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर ने उन्हें आड़े हाथों लिया।

राजभर ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को लंबा समय हो गया है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव कभी दर्शन करने नहीं गए। उनके जिम्मे कोई काम नहीं है। उनको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार राम मंदिर पर का कोई अधिकार नहीं है। उसके लिए ट्रस्ट बना है। यदि ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है तो जांच करा दीजिए। इसके बाद राज्य सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है, जांच हो रही है। जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज और जिले के प्रभारी मंत्री राजभर ने शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। अंबेडकरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा ने बीते दिनों राजभर को गालीबाज कहा था, ओम प्रकाश राजभर ने इस पर कहा कि लालजी तो दलबदलू नेता हैं। उनको मौका मिलेगा तो भाजपा में चले जाएंगे।

सपा के टूटने के सवाल पर राजभर ने कहा कि टीएमसी टूटी और शिवसेना टूटी, किसी को भरोसा तो नहीं था। इसी तरह से सपा भी टूटेगी। समाजवादी पार्टी जैसा धोखेबाज दल तो कोई हो ही नहीं सकता।

सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल के उस बयान पर मंत्री ने करारा जवाब दिया कि जहां से राजभर लड़ेंगे, वे वहीं लड़ेंगे। इस पर बोले कि कि दम है तो शिवपाल सिंह यादव गाजीपुर के जहूराबाद में खुद आकर लड़ लें। एक समय था शिवपाल को निकाल दिया था। मंच से धक्का देकर निकाल दिया गया था। उनको तो सपा में तिरछी नजर से देखा जा रहा है। अब तो सपा से दो दगे कारतूस मिलकर चुनाव लड़ेंगे।

कॉमन सर्विस सेंटरों पर पीएम किसान उत्सव दिवस का सफल आयोजन

सुल्तानपुर। भारत सरकार एवं सीएससी एसपीवी के निर्देशानुसार रविवार को जनपद सहित प्रदेशभर के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) केंद्रों पर ष्पीएम किसान उत्सव दिवसष् का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने सीएससी केंद्रों पर एकत्र होकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 23वीं किस्त जारी होने के अवसर के साक्षी बने। इस अवसर पर सीएससी केंद्रों पर किसानों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण प्रदर्शित किया गया। किसानों ने सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास एवं किसान कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की सराहना की। कार्यक्रम के उपरांत बड़ी संख्या में पात्र किसानों ने अपने बैंक खातों में प्राप्त सम्मान निधि की राशि का डिजीपे वेब के माध्यम से

न्यू टाउनशिप के लेआउट के लिए फिर टेंडर आमंत्रित करेगा मेडा, एक सप्ताह पहले निरस्त हुआ था टेंडर

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। न्यू टाउनशिप का लेआउट बनाने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) फिर से टेंडर आमंत्रित करेगा। इसके लिए पांच जून को आइक्यूटी कंपनी का चयन कर लिया गया था, लेकिन अब उस पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। इसमें एक कंपनी पर झूठे दस्तावेज जमा करने का आरोप है।

मेडा ने हाल ही में लेआउट बनाने के लिए टेंडर आमंत्रित किया था। उसमें तीन कंपनियों आइक्यूटी प्रा. लि. दिल्ली, एमएसवी इंटरनेशनल गुरुग्राम, नांगिया एंड कंपनी एलएलपी दिल्ली ने टेंडर डाला। कंपनी का चयन होने के बाद मेडा को शिकायत मिली कि प्रतिभागी कंपनियों में से एक ने झूठे दस्तावेज लगाकर टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। हालांकि संबंधित कंपनी को कार्य का आवंटन नहीं हुआ, इसलिए प्रक्रिया को बरकरार रखा जा सकता था। इस स्थिति में कम से कम तीन टेंडर का मानक पूरा नहीं हो पाता, इसलिए मेडा ने पूरी टेंडर प्रक्रिया ही निरस्त कर दी। संबंधित निरस्तीकरण के लिए मेडा के मुख्य नगर नियोजक तेज प्रताप सिंह ने सूचना जारी कर दी है।

नए पंजीकरण शासनादेश के विरोध में उतरे दस्तावेज़ लेखक, आंदोलन की दी चेतावनी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। तहसील सदर में शनिवार को दस्तावेज़ लेखक संघ की आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंजीकरण एवं निबंधन विभाग द्वारा जारी नए शासनादेश का विरोध करते हुए इसे रोजगार विरोधी बताया गया। बैठक के बाद संघ ने सपा प्रवक्ता व पूर्व विधायक अनूप संडा के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांगपत्र भेजा।

संघ के अनुसार 4 जून को जारी शासनादेश के तहत जमीन और अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया को निजी संस्थाओं के माध्यम से संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। दस्तावेज़ लेखकों का कहना है कि इससे प्रदेशभर में इस कार्य से जुड़े अधिवक्ता, बैनामा लेखक, स्टांप विक्रेता, कंप्यूटर ऑपरेटर और मुंशी जैसे लाखों लोगों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार रोजगार सृजन की बात करती है, लेकिन यह निर्णय बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा कर सकता है। इस दौरान सपा प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि लगातार निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने दस्तावेज़ लेखकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में उनका योगदान लंबे समय से रहा है और व्यवस्था में बदलाव से उनकी आजीविका प्रभावित हो सकती है। संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शासनादेश वापस नहीं लिया गया तो तहसील सदर के दस्तावेज़ लेखक, स्टांप विक्रेता और संबंधित कर्मचारी अनिश्चितकाल के लिए रजिस्ट्रेशन कार्य का बहिष्कार कर सकते हैं। बैठक में पीयूष तिवारी, अजीम किदवई, श्याम बहादुर सिंह, मो. अकरम, अच्छे लाल यादव समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी जन सेवा केन्द्रों में होगा सामूहिक योगाभ्यास

सुल्तानपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश में जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से व्यापक स्तर पर योग जागरूकता अभियान और सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य योग को जन-आंदोलन का स्वरूप देना तथा स्वस्थ, जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण में जन सेवा केन्द्रों की भूमिका को और अधिक मजबूत बनाना है। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को योग के प्रति जागरूक किया जाएगा तथा उन्हें नियमित योगाभ्यास अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 7 बजे से सभी जन सेवा केन्द्रों पर प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग प्रधानमंत्री के संबोधन और कार्यक्रम का सामूहिक रूप से अवलोकन कर सकेंगे।

डेढ़ साल से टूटा नहीं हौसला, पर क्या इस बरसात में भी तरिपाल के नीचे कटेगी 1.40 लाख परिवारों की जिंदगी?

आर्यावर्त संवाददाता

शाहजहांपुर। सदर तहसील के बाडीगांव निवासी आसमा ने छह माह पहले प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उनका चयन नहीं हुआ। चार बच्चों के साथ कच्चे मकान में तिरपाल के नीचे रह रहीं आसमां अकेली नहीं हैं। प्रचंड गर्मी में पंखे के बिना एक पल भी बैठना मुश्किल है। चटख धूप परेशान कर रही है।

तमाम लोग ऐसे हैं, जिन्हें तिरपाल या टिनशेड के नीचे परिवार के साथ रहना पड़ रहा है। गर्मी तो किसी तरह कट भी जाएगी, लेकिन छप्परदार कच्चे मकानों में बरसात के दौरान होने वाली दिक्कतों को लेकर ग्रामीण अभी से चिंतित हैं।

इनके सिर पर पक्की छत के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन मांगे गए थे, लेकिन डेढ़ वर्ष में एक भी नया आवास नहीं बना। क्योंकि केंद्र से कोई लक्ष्य ही नहीं दिया गया। लगभग एक लाख 40 हजार परिवार इंतजार में हैं कि कब लक्ष्य आए और उनको आवास मिले। इसमें कितना समय लगेगा अधिकारी भी नहीं जानते।

दरअसल आवेदक के सत्यापन, चयन व धनराशि भेजने की प्रक्रिया भी लंबी है। इसलिए अगर अगले एक माह में बजट स्वीकृत भी हुआ तो लक्ष्य के सापेक्ष चयन व उसके बाद निर्माण की प्रक्रिया में साल भर लग जाएगा। ऐसे में इस बार की बरसात व सर्दी भी इन्हीं कच्चे मकानो में छप्पर, टिनशेड व तिरपाल के नीचे काटनी होगी। हालांकि ग्राम्य विकास अभिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है, जितने भी आवेदन हुए हैं उनमें कितने लोग पात्र हैं, इसके लिए गांव-गांव सत्यापन शुरू करा दिया गया है। यह प्रक्रिया 30 जून तक पूरी होने का दावा किया जा रहा है।

पति विक्रम मजदूरी करते हैं। हम लोगों के पास आय का कोई स्थायी साधन भी नहीं है। दो बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी को दृष्टि दोष है। छह माह से आवास के लिए प्रधान से लेकर बीडीओ कार्यालय के चक्कर लगा रही हूं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा।

- रीता देवी

पांच महीने पहले हमने आवास के लिए आवेदन किया था। पति का निधन हो चुका है। बच्चों के साथ कच्चे घर में किसी तरह जीवन यापन कर रही हूं। बरसात के समय सबसे ज्यादा दिक्कत होती है।

- नन्ही देवी, चौढरा

प्रधानमंत्री आवास के लिए डेढ़ वर्ष से कोई नया लक्ष्य नहीं आया है। इसलिए आवास स्वीकृत नहीं हो पा रहे। जो आवेदन आए हैं उनका सत्यापन कराया जा रहा है। लक्ष्य आते ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

- अवधेश राम, परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण

आमने-सामने बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत, दो गंभीर घायल

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुलतानपुर। बल्दीराय थाना क्षेत्र के कुड़वार-हलियापुर मार्ग पर सहजौरा मोड़ के पास स्थित असलम प्रधान की चक्की के निकट शनिवार को दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बल्दीराय पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस्माइलपुर मजरे दरियापुर निवासी अरुण कुमार कनौजिया (22) अपने छोटे भाई शैलेंद्र कनौजिया (19) के साथ बाराबंकी से किसी निमंत्रण कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक पर सवार इब्राहिमपुर निवासी शमीम (23) पुत्र युसूफ तथा फैजान पुत्र छोट्टन से उनकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में शैलेंद्र कनौजिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल शमीम ने इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। फैजान की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज लखनऊ में चल रहा है। वहीं अरुण कुमार कनौजिया गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल सुलतानपुर में किया जा रहा है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है।

दोबारा रिश्वत लेते धरा गया कानूनगो

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अयोध्या एंटी करप्शन टीम ने शनिवार को लंभुआ तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) राजितराम को ₹12,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई शहर के डाकखाना चौराहे के पास की गई, जिससे राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, मणिकापुर परासिन निवासी अजय कुमार ने अपनी जमीन के सीमांकन (पैमाइश) की आख्या भेजे जाने के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि इस काम को आगे बढ़ाने के एवज में राजस्व निरीक्षक राजितराम लगातार ₹12,000 की रिश्वत मांग रहे थे। बार-बार की मांग से परेशान होकर पीड़ति ने अयोध्या मंडल की एंटी करप्शन टीम से शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की पुष्टि के बाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन अयोध्या मंडल के निरीक्षक एवं ट्रैप टीम प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। तय योजना के तहत पीड़ति को केमिकल लगे नोट देकर भेजा गया। जैसे ही आरोपी कानूनगो ने शहर के डाकखाना चौराहे से गोसाईगंज रोड स्थित मिश्रा साहित्य निकेतन के सामने रिश्वत की रकम ली टीम ने तत्काल दबिश देकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को गोसाईगंज ले गई, जहां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मामले की विवेचना निरीक्षक हरिओम मिश्र को सौंपी गई है।

चौंकाने वाली बात यह है कि यह राजितराम की पहली गिरफ्तारी नहीं है। इससे पहले 13 दिसंबर 2023 को भी कादीपुर तहसील में कानूनगो रहते हुए वह ₹5,000 की रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ चुका है। उस मामले में शिकायत भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र उपाध्याय ने की थी। लगातार दूसरी बार रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तारी ने राजस्व विभाग की कार्यशैली और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पति की जान लेने को रोटी में मिलाई थी चूहे मारने की दवा, एक-दूसरे के प्यार में पागल देवर-भाभी भेजे गए जेल

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। प्रेम संबंधों में हत्या करने वाले देवर और भाभी को पुलिस ने शुक्रवार को जेल भेज दिया। भाभी से प्रेम संबंधों में आरोपित ने बुधवार को अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए गुरुवार की रात दोनों को गिरफ्तार किया था। युवती ने बताया कि रिश्ता तय होने के बाद वह और देवर से इंस्टाग्राम पर चैटिंग करने लगे। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए।

उसने दो महीने पहले भी पति को रोटी में चूहा मारने की दवा मिलाकर खिलाने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रही थी। सदर के सुल्तानपुरा निवासी अमित उर्फ सोलू का हत्या करके फेंका शव चिरौटी बाग में झाड़ियों में मिला था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर अमित के छोटे भाई भोले को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा मामला खुल गया।

हत्या की साजिश में शामिल अमित की पत्नी खुशी को भी गिरफ्तार कर लिया। खुशी ने बताया कि छह महीने पहले उसका रिश्ता अमित के साथ तय हुआ था। इसी दौरान देवर से बातचीत के दौरान उसका नंबर ले लिया। दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर गहरी मित्रता हो गई। वह अमित की जगह भोला को पसंद करने लगी। अमित से शादी के बाद भी दोनों के संबंध बरकरार रहे। वह और भोला साथ रहना चाहते थे।

मगर, अमित के जीवित रहते यह संभव नहीं था। इसलिए दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। अमित के स्वजन ने पुलिस को बताया कि दो महीने पहले भी खुशी ने पति को रोटी में चूहे मारने की दवा देकर खिलाने का प्रयास किया था। मगर, पति-पत्नी के बीच किसी बात पर विवाद हो गया और अमित ने खाना नहीं खाया। इंस्पेक्टर विजय विक्रम सिंह ने बताया कि हत्यारोपित खुशी और भोला को जेल भेजा गया है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला : सवालों के घेरे में बैंक कर्मियों की भूमिका, क्यों खामोश रहा सिस्टम?

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर की दान राशि में कथित हेराफेरी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इस मामले के नए पहलू सामने आ रहे हैं। अब जांच की सुई केवल गणना करने वाले कर्मचारियों या ट्रस्ट से जुड़े लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। SIT को जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं, जिनसे बैंकिंग व्यवस्था की गंभीर चूक और संभावित मिलीभगत की आशंका मजबूत हुई है।

दिलचस्प बात यह है कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेन्द्र मिश्रा भी पहले इस मुद्दे पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में पूछा था कि आखिर दान राशि की गणना और जमा प्रक्रिया में शामिल बैंकिंग तंत्र को अनियमितताओं की भनक क्यों नहीं लगी।

गिनती कक्ष में बैंक की भी थी बराबर जिम्मेदारी

दरअसल दानपात्रों से निकलने वाली नकदी की गणना केवल ट्रस्ट या मंदिर कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया में संबंधित बैंक के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहते हैं। उनकी भूमिका यह सुनिश्चित करने की होती है कि नकदी की गिनती, मिलान और जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियम के मुताबिक हो। लेकिन जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जिस तरह लंबे समय तक कथित हेराफेरी चलती रही, उससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बैंकिंग निगरानी तंत्र आखिर कहां था। अगर गणना के दौरान रकम में अंतर आ रहा था तो उसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं हुई और जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई।

निजी कंपनी के जरिए चल रही थी व्यवस्था

सूत्रों के अनुसार, नकदी गणना का काम बैंक ने एक निजी एजेंसी को सौंप रखा था। यह एजेंसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति करती थी और उन्हें गणना कार्य में लगाती थी। जांच में सामने आया है कि गणना प्रक्रिया में शामिल कई लोगों की नियुक्ति प्रभावशाली लोगों की सिफारिश पर हुई थी। आरोप है कि ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों के रिश्तेदार, परिचित और उनके करीबी लोग भी इस व्यवस्था का हिस्सा बने। ऐसे में गणना प्रक्रिया की निष्पक्षता और निगरानी दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

प्रभाव के आगे बेबस दिखे बैंक अधिकारी

जांच से जुड़े सूत्र बताते हैं कि ट्रस्ट से जुड़े प्रभावशाली पदाधिकारियों की पहुंच और दबदबे के कारण बैंक अधिकारी भी सख्ती से नियम लागू नहीं कर पाए। मंदिर की व्यवस्था से जुड़े निर्णयों पर उनका प्रभाव इतना अधिक था कि बैंक कर्मी अक्सर केवल औपचारिक भूमिका निभाते नजर आए। कई अधिकारियों को कथित अनियमितताओं की जानकारी होने या संदेह होने के बावजूद उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। यही वजह है कि अब SIT यह पता लगाने में जुटी है कि यह केवल लापरवाही का मामला था या फिर जानबूझकर आंखें मूंद लेने की रणनीति अपनाई गई थी।

SIT खंगाल रही जिम्मेदारी की पूरी श्रृंखला

जांच एजेंसी अब यह समझने की कोशिश कर रही है कि दान राशि की गिनती से लेकर बैंक में जमा होने तक की पूरी प्रक्रिया में किस स्तर पर चूक हुई। यदि बैंक अधिकारियों की भूमिका केवल प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित रही तो मामला अलग होगा, लेकिन यदि किसी स्तर पर मिलीभगत या संरक्षण के प्रमाण मिले तो जांच का दायरा और बढ़ सकता है। राम मंदिर दान राशि प्रकरण में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब गिनती कक्ष में ट्रस्ट, बैंक और आउटसोर्सिंग एजेंसी तीनों मौजूद थे, तब कथित हेराफेरी का खेल आखिर इतने लंबे समय तक बिना रोक-टोक कैसे चलता रहा।

बैंक के एक अधिकारी समेत 3 से 4 लोगों की भूमिका संदिग्ध

सूत्रों के मुताबिक, जब ट्रस्ट के कर्मचारी अपनी मनमर्जी से पूरी प्रक्रिया संचालित करते थे तो उसका फायदा कृछ बैंक कर्मियों ने भी उठाया। आशंका है कि कछ कर्मचारी सीधे तौर पर इसमें शामिल रहे हो। वहीं एक बैंक अधिकारी की भी संलिप्तता सामने आ रही है, जो ट्रस्ट के एक पदाधिकारी के घर पर किराए पर रहते हैं। सूत्रों का कहना है कि SIT को इससे संबंधित कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, जिनकी तस्दीक की जा रही है। SIT की जांच का अगला चरण इसी सवाल का जवाब तलाशने पर केंद्रित है।

सेवा और संवेदना की मिसाल बना सेवार्थम फाउंडेशन, बेटियों की शादी में किया सहयोग

चांदा/सुल्तानपुर। समाज के कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के सहयोग के लिए लगातार कार्य कर रहा सेवार्थम फाउंडेशन एक बार फिर मददगार बनकर सामने आया है। फाउंडेशन ने क्षेत्र के दो परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। चांदा क्षेत्र के मनीपुर गांव स्थित यादव बस्ती में एक जरूरतमंद परिवार की बेटी के विवाह के लिए सेवार्थम फाउंडेशन की ओर से 11 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वहीं मल्हीपुर गांव की निषाद बस्ती निवासी अनिल निषाद के परिवार में बेटी के विवाह के अवसर पर 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता के साथ अलमारी भेंट की गई।इस अवसर पर फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि बेटियों की शादी हर परिवार के लिए खुशी का पल होता है।

ललितपुर को मिली 1766 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

हमारे लिए 25 करोड़ जनता ही परिवार: मुख्यमंत्री योगी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद को विकास की बड़ी सौगात देते हुए 1766 करोड़ रुपये की 221 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तुवन मंदिर मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ललितपुर का तेजी से बदलता स्वरूप इसका प्रमाण है। उन्होंने विपक्षी दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने वर्षों तक शासन किया, लेकिन ललितपुर जैसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए।मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ललितपुर को एक साथ 1500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का

लाभ मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने पांच दशक और समाजवादी पार्टी ने कई बार प्रदेश में सरकार चलाई, लेकिन दोनों दल मिलकर भी ललितपुर को इतना विकास नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि सपा के लिए सैफई और कांग्रेस के लिए दिल्ली का एक परिवार ही सब कुछ था, जबकि भाजपा सरकार के लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता परिवार है और उनके विकास, सुरक्षा तथा सम्मान की जिम्मेदारी सरकार की है।उन्होंने कहा कि एक समय था जब बुंदेलखंड के नौजवान रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर थे। क्षेत्र में न उद्योग थे, न रोजगार के अवसर और न ही पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं। आज वही बुंदेलखंड विकास, निवेश और रोजगार का केंद्र बन रहा है। प्रदेश सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के कारण यहां के युवा और बेटियां उत्तर प्रदेश पुलिस सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित हो रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण ललितपुर वर्षों तक विकास से वंचित रहा। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। महिलाएं पानी के लिए लंबी दूरी तय करने को विवश थीं और अवैध खनन तथा वन संपदा की लूट आम बात थी। लेकिन अब हर घर जल योजना के माध्यम से लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है और सिंचाई परियोजनाओं के कारण किसानों की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है।योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ललितपुर अब केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि नवाचार और विकास के लिए भी पहचाना जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का पहला औषधि निर्माण उद्यान (फार्मा पार्क) लगभग 1500 एकड़ भूमि में ललितपुर में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि भविष्य में यहां आयुष आधारित औद्योगिक पार्क भी विकसित किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, रक्षा औद्योगिक गलियारा और अन्य आधारभूत परियोजनाएं इस क्षेत्र को नई पहचान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा औद्योगिक गलियारे के तहत प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है, जो देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है और इसका लाभ बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों को भी मिल रहा है।मुख्यमंत्री ने अर्जुन सहायक परियोजना सहित कई सिंचाई योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि दशकों से लंबित परियोजनाओं को उनकी सरकार ने पूरा कराया है। रतौली बांध, बावनी बांध, कचनौदा बांध और अन्य योजनाओं से किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा मिल रही है, जिससे उनकी आय में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि समग्र विकास ही समाज को आगे बढ़ा सकता है और इसके लिए किसानों, युवाओं, व्यापारियों, कारीगरों तथा महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना आवश्यक है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री युवा योजना के माध्यम से युवाओं को बिना ब्याज और गारंटी के आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है ताकि वे अपना उद्यम स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकें।

एआई और बदलती तकनीक के दौर में जीवनभर सीखने की क्षमता सबसे जरूरी : डब्ल्यूपीयू गोवा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और तेजी से बदलते तकनीकी परिवेश के बीच विश्वविद्यालयों को छात्रों को केवल पहली नौकरी के लिए तैयार करने के बजाय उन्हें पूरे जीवन में आने वाले करियर बदलावों और नई चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना होगा। यह विचार वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी (डब्ल्यूपीयू) गोवा द्वारा आयोजित 'ओपन हाउस' कार्यक्रम में व्यक्त किए गए।20 जून को आयोजित इस कार्यक्रम में भावी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भविष्य की उच्च शिक्षा और बदलती दुनिया में विश्वविद्यालयों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि आज उद्योग जगत इतनी तेजी से बदल रहा है कि पारंपरिक शिक्षा मॉडल को भी समय के अनुरूप बदलना आवश्यक हो गया है।चर्चा का मुख्य केंद्र

डब्ल्यूपीयू गोवा का 'ट्रांसडिसिप्लिनरी' शिक्षा मॉडल रहा, जो किसी एक विषय की गहन जानकारी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सोचने, नई परिस्थितियों के अनुरूप ढलने और वास्तविक जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता विकसित करने पर आधारित है।विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वाल्टर लील ने कहा कि डब्ल्यूपीयू गोवा की स्थापना ऐसे शैक्षणिक दृष्टिकोण के साथ की जा रही है, जो छात्रों और शिक्षकों को विषयों की सीमाओं से बाहर निकलकर सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि यहां शिक्षा के साथ व्यावहारिक अनुभव, उद्योग जगत से जुड़ाव, वैश्विक दृष्टिकोण और स्व-अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता है, ताकि विद्यार्थी जीवनभर सीखने और नेतृत्व करने के लिए तैयार हो सकें।प्रो-वाइस चांसलर डॉ. आशीष भारद्वाज ने कहा कि भविष्य केवल विशेषज्ञों का नहीं होगा, बल्कि उन लोगों का होगा जो निरंतर सीख सकें।

मोबाइल झपटमार गिरफ्तार, लूटा गया विवो मोबाइल बरामद; 24 घंटे के भीतर मदेयगंज पुलिस को सफलता

लखनऊ। मदेयगंज थाना पुलिस ने मोबाइल झपटमारी की घटना का त्वरित खुलासा करते हुए एक शातिर झपटमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार फैजुल्लागंज निवासी 24 वर्षीय मानसी कुमारी ने 19 जून 2026 को थाना मदेयगंज में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति उनका विवो वाई-16 मोबाइल फोन झपट्टा मारकर फरार हो गया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।मामले की विवेचना कर रहे उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार तिवारी ने पुलिस टीम के साथ आरोपी की तलाश शुरू की।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 'मां एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए योग' पुस्तिका का विमोचन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) लखनऊ और सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से 'मां एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए योग' नामक विशेष पुस्तिका का विमोचन किया। विकास भवन स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुस्तिका का लोकार्पण जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रेयस मौर्य ने किया।यह पहल 'सेहतमंद आदतें' कार्यक्रम के अंतर्गत की गई है, जिसे एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कंपनी का सहयोग प्राप्त है। माताओं, बच्चों और किशोरियों के समग्र स्वास्थ्य एवं कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार की गई यह पुस्तिका गर्भवती महिलाओं, शिशु की देखभाल करने वाली माताओं, किशोरियों तथा तीन से छह वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित, वैज्ञानिक और व्यवहारिक योग अभ्यासों पर आधारित है।कार्यक्रम में सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट के कार्यक्रम समन्वयक आशीष शुक्ला सहित संस्था के अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर योग को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य तथा समग्र विकास से जोड़ते हुए इसके लाभों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया।पुस्तिका का विमोचन करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रेयस मौर्य ने कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ-साथ स्वस्थ और संतुलित जीवन का प्रभावी माध्यम भी है।

गोरखपुर जंक्शन पर एलईडी वॉटर फाउंटेन बने आकर्षण का केंद्र, स्टेशन सौंदर्यीकरण को मिली नई पहचान

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर एवं अपर महाप्रबंधक विनोद कुमार शुक्ल के मार्गदर्शन में लखनऊ मंडल द्वारा गोरखपुर जंक्शन स्टेशन के सौंदर्यीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने तथा स्टेशन को आधुनिक एवं आकर्षक स्वरूप देने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म संख्या 01 और 09 पर अत्याधुनिक एलईडी लाइटिंग से सुसज्जित आकर्षक वॉटर फाउंटेन स्थापित किए गए हैं रंग-बिरंगी रोशनी के साथ लहराती और गिरती जलधाराएं यात्रियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। दिन और रात दोनों समय इन फाउंटेन की मनमोहक छटा स्टेशन परिसर को नई पहचान दे रही है। विशेष रूप से रात्रि के समय एलईडी प्रकाश से जगमगाते फाउंटेन यात्रियों और आगंतुकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यही कारण है कि ये फाउंटेन अब यात्रियों के बीच लोकप्रिय सेल्फी प्वाइंट के रूप में भी उभरकर सामने आए हैं मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बताया कि रेलवे द्वारा संचालित 'स्वच्छ व सुंदर स्टेशन' अभियान के अंतर्गत स्टेशन परिसर को अधिक आकर्षक और यात्री-अनुकूल बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में फाउंटेन के आसपास के क्षेत्र को भी विशेष रूप से विकसित किया गया है, जिससे यात्रियों को स्वच्छ, सुंदर और सुखद वातावरण उपलब्ध हो सके।उन्होंने कहा कि गोरखपुर जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे का प्रमुख स्टेशन होने के साथ-साथ लाखों यात्रियों की आवाजाही का केंद्र है।

पेड़ों की सुरक्षा के लिए लगाए गए लोहे के ट्री गार्ड चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 10 ट्री गार्ड बरामद

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के महानगर थाना क्षेत्र में पेड़ों की सुरक्षा के लिए लगाए गए लोहे के ट्री गार्ड चोरी कर बेचने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 10 ट्री गार्ड बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 18 हजार रुपये बताई गई है। मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।पुलिस के अनुसार शहरी वन क्षेत्र लखनऊ के वन रक्षक योगेश कुमार अपनी टीम के साथ दो आरोपियों को पकड़कर थाना महानगर लाए। उन्होंने तहरीर देकर बताया कि आरोपियों ने कुल 28 लोहे के ट्री गार्ड चोरी कर बेच दिए हैं तथा 10 ट्री गार्ड के साथ पकड़े गए हैं। शिकायत के आधार पर थाना महानगर में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई।जांच के दौरान नामजद आरोपी संजू कश्यप

पुत्र मेवा लाल कश्यप निवासी तकिया निशातगंज तथा पवन कश्यप पुत्र विपत कश्यप निवासी बाबा का पुरवा, पेपरमिल कॉलोनी, निशातगंज को पुलिस हिरासत में लिया गया। पूछताछ और तलाशी के दौरान उनके कब्जे से मुकदमे से संबंधित 10 चोरी किए गए लोहे के ट्री गार्ड बरामद हुए।पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर लोहे के ट्री गार्ड चोरी करते थे और उन्हें बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। बरामद ट्री गार्ड की कीमत लगभग 18 हजार रुपये आंकी गई है। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि मामले में सहादत अली नामक एक अन्य आरोपी की भूमिका भी सामने आई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।इस कार्रवाई को उपनिरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद, आरक्षी प्रवीण कुमार तथा आरक्षी नमन कुमार की टीम ने अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति की चोरी और नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ट्री गार्ड शहर में लगाए गए पौधों और वृक्षों की सुरक्षा के लिए स्थापित किए जाते हैं। उनकी चोरी न केवल सरकारी संपत्ति का नुकसान है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी प्रभावित करती है। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

महाकुंभ 2025 की ऐतिहासिक गाथा बनी पुस्तक, 'श्रद्धालु 66 करोड़ के पार' का लखनऊ में भव्य विमोचन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। महाकुंभ 2025 के दौरान 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भागीदारी, कुशल प्रशासनिक प्रबंधन और सुचारु व्यवस्थाओं को अब एक प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में पुस्तक का रूप दिया गया है। शनिवार को राजधानी लखनऊ के होटल ताज में आयोजित एक गरिमामय समारोह में पुस्तक "महाकुंभ 2025 : श्रद्धालु 66 करोड़ के पार" का भव्य विमोचन किया गया। समारोह में न्यायपालिका, प्रशासन, साहित्य, पत्रकारिता और धार्मिक जगत की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों ने सहभागिता की।प्रयागराज निवासी लेखक एवं शोधकर्ता डॉ. गोविंद कुमार सक्सेना द्वारा लिखित इस पुस्तक में महाकुंभ 2025 को केवल एक धार्मिक आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, सुशासन, तकनीकी नवाचार और

सामाजिक सहभागिता के विराट संगम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, यातायात संचालन, स्वच्छता व्यवस्था, डिजिटल तकनीक के उपयोग और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों का विस्तार से वर्णन किया गया है।समारोह के मुख्य अतिथि पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने कहा कि महाकुंभ भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक एकता का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक आयोजनों का प्रामाणिक दस्तावेजीकरण आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य संदर्भ सामग्री सिद्ध होता है। न्यायमूर्ति सिंह ने पुस्तक में महाकुंभ के विविध आयामों को समाहित किए जाने की सराहना करते हुए इसे महत्वपूर्ण शोधपरक प्रयास बताया।कार्यक्रम की अध्यक्षता लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 ने यह सिद्ध कर दिया कि जब सुशासन, आधुनिक तकनीक और जनसहयोग एक साथ कार्य करते हैं तो असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी सफलतापूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित अनुभव प्रदान करने के पीछे हजारों कर्मियों तथा विभिन्न विभागों का अथक और समन्वित प्रयास रहा। आयुक्त ने कहा कि डॉ. गोविंद कुमार सक्सेना ने इस पुस्तक के माध्यम से महाकुंभ के व्यवस्थागत, सामाजिक और आध्यात्मिक पक्षों को एक साथ प्रस्तुत कर इस ऐतिहासिक आयोजन की स्मृतियों को स्थायी रूप से संरक्षित करने का सराहनीय कार्य किया है।समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (न्याय) एवं विधिक परामर्शी उदय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व संपादक रतन मणि लाल, पंचदशनाम जूना अखाड़ा, महाशक्ति पीठ कल्याणपुर कानपुर की महामंडलेश्वर मां योग योगेश्वरी यति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु शेखर सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध कवि एवं विधि प्राध्यापक डॉ. श्लेष गौतम ने किया।पुस्तक के लेखक डॉ. गोविंद कुमार सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा कि महाकुंभ भारत की सनातन आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। उन्होंने बताया कि पुस्तक लिखने का उद्देश्य केवल घटनाओं का संकलन नहीं, बल्कि उस दिव्य अनुभव को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना है जिसे करोड़ों श्रद्धालुओं ने प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के 1.42 करोड़ विद्यार्थी करेंगे योग, 1.32 लाख विद्यालयों में विशेष आयोजन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। 21 जून को प्रदेश के 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 1.42 करोड़ छात्र-छात्राएं तथा 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की 78 हजार से अधिक छात्राएं सामूहिक योगाभ्यास में भाग लेंगी। योग को जन-जन तक पहुंचाने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं।प्रदेश भर के विद्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक तथा अभिभावक भी सहभागिता करेंगे। कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन, अनुश्रवण और समन्वय के लिए शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखकर जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयुष मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों तथा खंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग का लक्ष्य है कि योग दिवस केवल औपचारिक आयोजन न रह जाए, बल्कि विद्यार्थियों के जीवन में स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच का स्थायी संदेश बनकर स्थापित हो।21 जून को विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही योग के महत्व पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिनमें विद्यार्थियों को योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों की जानकारी दी जाएगी। विद्यालयों को स्थानीय समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि योग का संदेश समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंच सके।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले वर्षों के दौरान प्रदेश में योग को विद्यालयी शिक्षा और जनस्वास्थ्य से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। नियमित योग गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, अनुशासन, एकाग्रता और आत्मविश्वास विकसित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसका सकारात्मक प्रभाव विद्यालयी वातावरण और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में भी देखने को मिला है।सरकार का मानना है कि आज की प्रतिस्पर्धी जीवनशैली में योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक जीवन दृष्टि का माध्यम भी है।

संक्षेप

उल्टे हैं मरीज के आन्तरिक अंग : श्रीकृष्णा मिशन हास्पिटल में सफल आपरेशन

लखनऊ। श्रीकृष्णा मिशन हास्पिटल में चिकित्सकों की टीम ने एक जटिल आपरेशन के द्वारा मरीज को नया जीवनदान दिया। गौर विकास क्षेत्र के पतिला निवासी संदीप कुमार के पित्त की थैली में पथरी थी। जांच में पता चला कि संदीप के आन्तरिक अंग उल्टी दिशा में थे। चिकित्सकों के लिये यह चुनौतीपूर्ण था। दूरबीन विधि से संदीप का सफल आपरेशन किया गया। अब वह स्वास्थ्यलाभ ले रहा है। वरिष्ठ सर्जन डा. नवीन मौर्य, एमडी एनेस्थीसिया डा. असरार अहमद की टीम ने सफल आपरेशन किया। चेयरमैन बसन्त चौधरी ने बताया कि श्रीकृष्णा मिशन हास्पिटल की स्थापना जिन उद्देश्यों से किया गया था वह निरन्तर साकार हो रहा है और चिकित्सकों की टीम नये आयाम विकसित कर रही है। यह बड़ी उपलब्धि है।

पैतृक जमीन के बंटवारे के विवाद में बेटे ने फावड़े से किया हमला, पिता की मौत

लखनऊ। राजधानी के महिगवां थाना क्षेत्र में पैतृक भूमि के बंटवारे को लेकर हुए पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ग्राम अतरौरा में बेटे द्वारा फावड़े से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल पिता की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार ग्राम अतरौरा निवासी रामकुमार यादव और उनके पुत्र महेंद्र यादव के बीच पैतृक भूमि के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। शुक्रवार 19 जून को रामकुमार यादव अपने खेत में खड़ी करवी (झाड़ियों) को ट्रैक्टर से जुतवा रहे थे। इसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।आरोप है कि विवाद के दौरान महेंद्र यादव ने फावड़े से अपने पिता रामकुमार यादव के सिर पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रामकुमार को परिजन तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) लखनऊ रेफर कर दिया गया।केजीएमयू में उपचार के दौरान रामकुमार यादव ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।

गोमती नदी में मिला अज्ञात महिला का शव, पहचान में जुटी पुलिस

लखनऊ। राजधानी के चौक थाना क्षेत्र में शनिवार को गोमती नदी से एक अज्ञात महिला का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने तथा मृत्यु के कारणों की जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार थाना चौक क्षेत्र स्थित गौतम बुद्ध पार्क के पीछे गोमती नदी में एक महिला का शव बहते हुए दिखाई देने की सूचना मिली थी। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और निरीक्षण के दौरान नदी के किनारे लगभग 35 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया। बताया गया कि शव नदी के बहाव के साथ किनारे पर आकर रुक गया था।प्रारंभिक जांच में मृतका लाल रंग के वस्त्र पहने हुए मिली। पुलिस को मृतका के बाएं हाथ पर रोमन लिपि में 'सोनम' तथा 'लव मा' अंकित गोदना भी मिला है, जिसे पहचान का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ के बावजूद महिला की पहचान नहीं हो सकी।पुलिस ने स्थानीय निवासियों, गोताखोरों और आसपास के लोगों से मृतका के संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। प्रथम दृष्टया शव पर किसी प्रकार के स्पष्ट बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं।

नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का हमला, अजय राय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और प्रश्नपत्र लीक के मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे प्रश्नपत्र लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं ने देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग की।अजय राय ने कहा कि वर्ष 2015 से लेकर 2026 तक कई बार राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ियों और प्रश्नपत्र लीक के मामले सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर प्रश्नपत्र लीक हुए, जिसकी जानकारी सामाजिक माध्यमों पर सार्वजनिक हुई। कांग्रेस और छात्र संगठनों के दबाव तथा विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार को परीक्षा निरस्त कर दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लेना पड़ा।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केवल नीट ही नहीं, बल्कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से लेकर उत्तर प्रदेश की लेखपाल भर्ती, उपनिरीक्षक भर्ती, पुलिस सिपाही भर्ती, समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती, कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं और सहायक प्राध्यापक भर्ती जैसी अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं भी प्रश्नपत्र लीक और अनियमितताओं की भेंट चढ़ चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं को निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था देने में पूरी तरह विफल रही है।अजय राय ने कहा कि नीट प्रश्नपत्र लीक प्रकरण के कारण उत्पन्न मानसिक तनाव से देश के विभिन्न राज्यों में कई छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने इन घटनाओं को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों ने छात्रों और अभिभावकों को गहरे मानसिक संकट में डाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में बिचौलियों और संगठित गिरोहों की भूमिका सामने आती रही है, लेकिन दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है।उन्होंने कहा कि पिछले बारह वर्षों में राष्ट्रीय स्तर की 23 प्रमुख परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आए हैं। इसके बावजूद परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार नहीं किए गए। कांग्रेस का आरोप है कि बार-बार होने वाली इन घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने में असफल रही है।अजय राय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए 'छात्रों की गूंज' अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देशभर के छात्रों की समस्याओं को सुनना और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए सुझाव जुटाना है।

योग है दुनिया के लिए भारत का शाश्वत अवदान

आज जब पूरी दुनिया युद्धों, आतंकवाद, हिंसा, मानसिक तनाव, पर्यावरणीय संकट और नई-नई बीमारियों की चुनौतियों से घिरी हुई है, तब मानवता एक ऐसे मार्ग की तलाश में है जो केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा को भी संतुलित कर सके। ऐसे संक्रमणकाल में योग केवल एक व्यायाम पद्धति या स्वास्थ्य विज्ञान नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के लिए आशा का प्रकाश-स्तंभ बनकर उभरा है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज केवल भारत का नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व का उत्सव बन गया है। भारत अनादिकाल से योग की भूमि रहा है। इस भूमि के कण-कण में ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और योगियों की साधना की सुगंध समाई हुई है। वैदिक ऋषियों से लेकर भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, श्री अरविन्द, आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ तक, सभी ने योग को जीवन के उत्कर्ष और मानव कल्याण का आधार माना। योग ने भारत की आध्यात्मिक चेतना को ही नहीं गढ़ा, बल्कि विश्व को यह संदेश भी दिया कि मनुष्य का वास्तविक विकास भीतर से प्रारंभ होता है।

आज विश्व जिस दिशा में बढ़ रहा है, वह चिंता का विषय है। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में संघर्ष, आतंकवाद की घटनाएं, साम्प्रदायिक तनाव और हथियारों की बढ़ती होड़ मानव सभ्यता को भय और असुरक्षा की ओर धकेल रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञान और तकनीक ने अभूतपूर्व सुविधाएं दी हैं, लेकिन इनके साथ विनाश की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। ऐसे समय में योग की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। योग मनुष्य को भीतर से शांत, संतुलित और संवेदनशील बनाता है। जब व्यक्ति के भीतर शांति होगी, तभी समाज और राष्ट्र में शांति का वातावरण निर्मित होगा। योग का मूल अर्थ ही है-जोड़ना। यह मनुष्य को मनुष्य से, आत्मा को परमात्मा से, व्यक्ति को समाज से और मानवता को सम्पूर्ण सृष्टि से जोड़ता है। योग विभाजन नहीं, एकता का दर्शन है। इसलिए वह हिंसा, घृणा, आतंक और संघर्ष का स्वाभाविक प्रतिरोधक है। जो व्यक्ति योग के माध्यम से अपने भीतर करुणा, प्रेम और अहिंसा का विकास करता है, वह किसी के प्रति द्वेष नहीं रख सकता। यही कारण है कि महात्मा गांधी की अहिंसा और भगवान महावीर का जीव-दया का संदेश भी योग की व्यापक चेतना से जुड़ा हुआ दिखाई देता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज मानसिक तनाव, अवसाद, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन भीतर से खाली और अशांत होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में योग एक समग्र चिकित्सा-पद्धति के रूप में सामने आया है। योग शरीर, मन और भावनाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। नियमित आसन, प्राणायाम और ध्यान व्यक्ति की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाते हैं, तनाव को कम करते हैं तथा मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी दुनिया ने अनुभव किया कि स्वस्थ जीवनशैली और मजबूत प्रतिरोधक क्षमता कितनी महत्वपूर्ण है। उस समय योग, प्राणायाम और ध्यान ने करोड़ों लोगों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी चिकित्सक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि योग अनेक बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन में अत्यंत प्रभावी सहायक माध्यम है। यह दवाओं का विकल्प नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन का आधार है।

योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल रोगों से मुक्ति नहीं देता, बल्कि जीवन को दिशा देता है। पातंजलि ने योग को "चित्तवृत्ति निरोध" कहा है। अर्थात् मन की चंचलता और विकारों पर नियंत्रण। जब मन नियंत्रित होता है, तब व्यक्ति में निर्णय क्षमता, धैर्य और आत्मविश्वास का विकास होता है। आज की पीढ़ी, जो तनाव, प्रतिस्पर्धा और डिजिटल व्यसनों के बीच जी रही है, उसके लिए योग मानसिक संतुलन का सबसे सशक्त माध्यम बन सकता है। योग का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका नैतिक और मानवीय आयाम भी है। यम और नियम जैसे सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, संयम और संतोष की शिक्षा देते हैं। यदि इन मूल्यों को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अपनाया जाए, तो हिंसा, भ्रष्टाचार, अपराध और सामाजिक विद्वेष जैसी समस्याओं में स्वाभाविक कमी आ सकती है। इसलिए योग केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और सामाजिक पुनर्निर्माण का भी अभियान है। भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता में योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाना भारत की सांस्कृतिक शक्ति और विश्वसनीयता का बड़ा प्रमाण है। आज दुनिया के लगभग सभी देशों में योग का अभ्यास किया जा रहा है। यह केवल एक कूटनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विक विजय है।

फाइबर अर्थव्यवस्था: भारत का अगला बड़ा वैश्विक अवसर

गिरिराज सिंह

अपशिष्ट से समृद्धि तक, स्थानीय प्रचुरता से वैश्विक अवसर तक — यही भारत की न्यू एज फाइबर मुहिम का सार है, जो हरित सामग्रियों और भविष्य के लिए तैयार वस्त्रों में भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर कर रहा है।

फाइबर के साथ भारत का 5,000 बरस पुराना सभ्यतागत संबंध है, जो हमारे गाँवों, परंपराओं तथा सामूहिक पहचान में गहराई से गुँथा है। बुनी हुई हवा कहलाने वाली मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध मलमल से लेकर समस्ते महाद्वीपों तक फैली भारतीय कारीगरी तक — फाइबर हमेशा से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा रहा है। आज, जब दुनिया वैश्विक स्थिरता की क्रांति की कगार पर खड़ी है, तब यही प्राचीन ज्ञान हमारी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति है।

दशकों तक केले के पेड़ के तने को बेकार अपशिष्ट मानकर फेंक दिया जाता था। आज वही बायोमास प्रीमियम फाइबर बनकर निर्यात बाज़ारों की मांग पूरी कर रहा है, ग्रामीण आजीविकाओं को सशक्त बना रहा है और इस कृषि अवशेष को राष्ट्रीय आय में बदल रहा है। अपशिष्ट से समृद्धि तक, स्थानीय प्रचुरता से वैश्विक अवसर तक — यही भारत की न्यू एज फाइबर मुहिम का सार है, जो हरित सामग्रियों और भविष्य के लिए तैयार वस्त्रों में भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर कर रहा है। न्यू एज फाइबर ऐसे टिकाऊ एवं पौधों-आधारित पदार्थ हैं, जो भारत के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक नवाचार के साथ जोड़ते हैं। बांस, भाँग, केला, पीएएलएफ, फ्लैक्स, रेमी, सिसल, मिल्कवीड और कपोक जैसे फाइबर सदियों से मौजूद रहे हैं, लेकिन अब इन्हें वस्त्र उद्योग, रक्षा, बायोडिग्रेडेबल कंपोज़िट्स और प्रीमियम उत्पादों में उच्च-मूल्य उपयोगों के लिए नए सिरे से खोजा जा रहा है। ये हरित भविष्य के लिए भारत के प्राकृतिक फाइबर भंडार का विस्तार कर रहे हैं। बढ़ती आय, वैश्विक स्थिरता संबंधी अनिवार्यताएँ और ट्रेसेबल सोर्सिंग की आवश्यकताएँ वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को पूरी तरह बदल रही हैं और एक नई फाइबर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही हैं। उपभोक्ता अब अपने पहनने के कपड़ों में आराम, पसीना सोखने की क्षमता या ब्रीदेबिलिटी और टिकाऊपन चाहते हैं। यही महत्वककपूर्ण बदलाव भारत में फाइबर की खपत को आज के 15 एमएमटी से बढ़ाकर 2030 तक 23 एमएमटी तक ले जाने वाला है। दुनिया अब तेजी से वही तलाश रही है, जिसे भारत प्रदान कर सकता है : नैतिक, टिकाऊ और उच्च-प्रदर्शन वाले प्राकृतिक फाइबर, जो सदियों के अनुभव पर आधारित हैं। इस विजन को एक स्पष्ट संस्थागत एवं नीतिगत ढाँचे का समर्थन प्राप्त है। वर्ष 2026-2031 के लिए 5,664 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाले मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत न्यू एज फाइबर्स के लिए 300 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान रखा गया है। इस प्रयास को और सशक्त बनाते हुए, केंद्रीय बजट 2026–27 में घोषित राष्ट्रीय फाइबर मिशन एक व्यापक रणनीतिक ढाँचा प्रदान करता है, जो चार प्रमुख स्तंभों : कृषि-सूत्र- खेती और कच्चे माल के विकास के लिए, इन्फिनिटी-अनुसंधान एवं नवाचार के लिए, ग्राम-सेतु - अवसंरचना और उद्यम सृजन के लिए, तथा जीएमपीएसः ब्रांडिंग और बाज़ार विकास के लिए - पर आधारित है । इस नीतिगत ढाँचे की शक्ति दशकों से जारी वैज्ञानिक अनुसंधान में निहित है, जिसे ठोस परिणाम पहले से ही सामने आ चुके हैं। मिल्कवीड (आक/मदार) जिसे पारंपरिक रूप से भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (एनआईटीआरए) में 18 वर्षों के अनुसंधान के बाद एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सामने आया है। अब इसका उपयोग रक्षा क्षेत्र में, विशेषकर –20एफ्ट तापमान में कार्यरत सैनिकों के लिए स्लीपिंग बैग बनाने में किया जा रहा है। ये स्लीपिंग बैग अपने पॉलिएस्टर विकल्पों की तुलना में 10त्न हल्के, ऊन से अधिक गर्म तथा सीएलओ/सेल प्रमाणित हैं। 55 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि पर बिना उर्वरक के उगाए जाने पर यह पौधा किसानों को प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 1.5–2 लाख रुपये तक की आय प्रदान करने की क्षमता रखता है। केले का फाइबर प्रतिवर्ष लगभग 1.8 मिलियन टन उत्पादन की क्षमता रखता है और कृषि अवशेषों से किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान कर सकता है, जबकि बांस प्रति हेक्टेयर 60 टन तक बायोमास उत्पादन करने की क्षमता रखता है, जिससे पूर्वोत्तर भारत के लिए बड़े अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। भाँग भी एक उभरता हुआ वैश्विक बाज़ार बन रहा है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जिसकी खेती की पहले से ही अनुमति है। फ्लैक्स, सिसल, रेमी, पीएएलएफ, बिछुआ या नेटल और कपोक जैसे फाइबरों के साथ मिलकर ये सभी भारत के टिकाऊ एवं प्राकृतिक फाइबर आधार का निरंतर विस्तार कर रहे हैं। इस वैज्ञानिक गति को आगे बढ़ाते हुए,न्यू एज फाइबर्स पर राष्ट्रीय सेमिनार एक ऐसे मंच के रूप में उभरा, जहाँ विज्ञान, नीति और उद्यम एक साथ आ सके। इसने शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, उद्यमियों, किसान संगठनों, उद्योग जगत के दिग्गजों और नीति-निर्माताओं को एक ही मंच पर एकत्रित किया। सभी दस प्राथमिकता प्राप्त फाइबर्स को कवर करने वाले तीन कार्य बलों की रिपोर्टें जारी की गईं, जिन्होंने क्षेत्रीय विज्ञान को सीधे योजनाओं के डिज़ाइन और निवेश की प्राथमिकताओं में बदल दिया। इस सेमिनार ने मानकों, प्रसंस्करण अवसंरचना और संस्थागत वित्तपोषण में मौजूद खामियों की भी स्पष्ट रूप से पहचान की , जो एक ऐसे मिशन को दर्शाता है जो केवल नीति नहीं, बल्कि वास्तविक क्रियान्वयन पर केंद्रित है। इसमें प्रमुख प्राथमिकताएँ: उत्पादन को पाँच वर्षों में 10,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 10 लाख मीट्रिक टन तक पहुँचाना, गुणवत्ता मानकों का विकास करना, मशीनरी के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना, आयातित प्रसंस्करण तकनीक पर निर्भरता कम करना और खेती से लेकर मूल्य संवर्धन तक क्लस्टर आधारित फाइबर इकोसिस्टम का निर्माण करना सामने आईं। ये सभी कदम मिलकर न्यू एज फाइबर्स को ग्रामीण समृद्धि और टिकाऊ विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मिशन बनाते हैं। शायद सबसे परिवर्तनकारी कार्य फाइबर ब्लेंडिंग है। भारत की वास्तविक शक्ति किसी एक फाइबर में नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से संयोजित करने में निहित है—जैसे थर्मल हल्केपन के लिए मिल्कवीड, गर्माहट के लिए ऊन, ब्रीदेबिलिटी के लिए बांस, और कोमलता के लिए कपास। मिश्रित कपड़ा या ब्लेंडेड फैब्रिक कोई समझौता नहीं है; यह प्रदर्शन को उन्नत बनाना है - ऐसे कपड़े तैयार करना जो अधिक मजबूत, अधिक स्मार्ट और अधिक टिकाऊ हों, साथ ही बेहतर आराम, नमी सोखने की क्षमता, टिकाऊपन तथा फैशन, जीवनशैली और तकनीकी वस्त्रों में बहुपयोगिता प्रदान करें। इसके लाभ पूरी मूल्य शृंखला में फैलते हैं। उपभोक्ताओं को बेहतर आराम और कार्यक्षमता मिलती है, निर्माताओं को प्रीमियम और विशिष्ट उत्पाद विकसित करने का अवसर मिलता है, और किसानों को विविध प्रकार की मांग तथा अधिक मजबूत आय प्राप्त होती है। भारत के लिए, ब्लेंडिंग या मिश्रण केवल एक तकनीकी नवाचार भर नहीं है; यह कच्चे फाइबर आपूर्ति से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, मूल्य-संवर्धित और भारतीय पहचान से जुड़े ब्रांड्स तक पहुँचने का एक सेतु है। असल में, न्यू एज फाइबर मुहिम जीवन को रूपांतरित करने, किसानों के लिए अवसर सृजित करने, ग्रामीण आजीविकाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं को सशक्त करने और उद्यमियों को स्थानीय संसाधनों से वैश्विक व्यवसाय खड़ा करने में सक्षम बनाने के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्रक मोदी के 5एफ विज़न—खेत से फाइबर, कपड़े से फैशन और विदेश तक—से प्रेरित, भारत की ग्रीन फाइबर क्रांति कोई दूर का सपना नहीं है। रणनीति तय है, संस्थान सक्रिय हैं, विज्ञान प्रमाणित हो चुका है, और उद्यमी तैयार हैं। आज भारत जो कर रहा है—फाइबर दर फाइबर, मिश्रण दर मिश्रण, क्षेत्र दर क्षेत्र, और खेत दर खेत—अपनी वस्त्र गाथा का अगला महान अध्याय लिख रहा है।

(लेखक केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं)

टिप्पणी

मानवीय त्रासदी की आखिर चिंता किसे

बड़े पर्यटन स्थल के रूप में उभरने की भारत की महत्त्वाकांक्षा पहले ही चोटिल हो चुकी है। अब ये धारणा बनी कि यहां सुरक्षित स्थितियां नहीं हैं, तो मेडिकल टूरिज्म भी प्रभावित हो सकता है।

दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुए अग्निकांड ने राष्ट्रीय राजधानी में आम प्रशासन के ध्वस्त हो चुके सिस्टम की पोल खोली है। इस दर्दनाक घटना में 21 लोगों की जान गई, जिनमें दर्जन भर विदेशी हैं। दिल्ली में बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) स्कीम के तहत आवासीय इलाकों में मकानों को होटल की तरह चलाने की छूट मिली हुई है। मगर, इसके लिए नियम और शर्तें तय हैं। बुधवार को हुए हादसे ने बताया कि इन नियम- शर्तों की किस धड़ल्ले से और कितना बेखौफ होकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस बीएंडबी होटल में आग लगी, उसे छह कमरे देने की इजाजत थी, मगर वहां 26 कमरों में आगंतुक रखे जा रहे थे।

फायर संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की जरूरत उसके मालिक नहीं समझी थी! और अब यह साफ है कि दिल्ली सरकार या एमसीडी के अधिकारियों ने निगरानी या औचक निरीक्षण की या तो जरूरत नहीं समझी, या फिर उनकी मिलीभगत से यह गोरखधंधा चल रहा था। अब मीडिया रिपोर्टों से यह भी साफ है कि उस इलाके में ऐसे अपने होटल चल रहे हैं। और उसी इलाके में क्यों, जब वहां ऐसा हो रहा है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा राष्ट्रीय राजधानी के अन्य इलाकों में भी चल रहा होगा! अग्निकांड का शिकार हुआ होटल एक बड़े प्राइवेट अस्पताल के पास है। उस अस्पताल में इलाज कराने आए लोगों के परिजन आस-पास के ऐसे ठिकानों पर ठहरते हैं।

भारत- खासकर दिल्ली कथित मेडिकल टूरिज्म का प्रमुख स्थल है, जहां मध्य, पश्चिम एवं दक्षिण एशिया, अफ्रीका और कुछ यूरोपीय देशों के मरीज भी इलाज कराने आते हैं। इस हादसे की खबर उन देशों में कैसा माहौल बनाएगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अभद्रता, महिलाओं से दुर्व्यवहार, गंदगी और बढ़ते प्रदूषण के कारण पर्यटन उद्योग के बड़े स्थल के रूप में उभरने की भारत की महत्त्वाकांक्षा पहले ही चोटिल हो चुकी है। अब ये धारणा बनी कि मरीज या उनके परिजनों के लिए यहां सुरक्षित स्थितियां नहीं हैं, तो मेडिकल टूरिज्म भी प्रभावित हो सकता है। मगर अपने यहां मानवीय त्रासदी और उनके दूरगामी परिणामों की आखिर चिंता किसे है!

ब्लॉग

सौ वर्षों से राष्ट्रसेवा में लीन आरएसएस का पंजीकरण प्रमाणपत्र मांग रहे कांग्रेस नेताओं से कुछ सवाल

नीरज कुमार दुबे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कांग्रेस और उसके वैचारिक सहयोगियों ने एक बार फिर वही पुराना शोर उठाया है कि संघ पंजीकृत क्यों नहीं है? कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे का पत्र और उसके बाद खड़ा किया गया राजनीतिक कोलाहल इस बात का प्रमाण है कि संघ विरोधियों के पास न तथ्य बचे हैं, न तर्क। वह केवल विवाद पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि जिस संगठन को जनता का भरोसा और समाज का समर्थन हासिल हो, उसे बदनाम करने का सबसे आसान तरीका संदेह फैलाना होता है।

लेकिन इस बार संघ ने भी स्पष्ट और सीधा उत्तर दिया है। मोहन भागवत ने साफ कहा, "हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है।" यह उस पूरी मानसिकता पर प्रहार है जो मानती है कि भारत की हर सांस्कृतिक चेतना को सरकारी मुहर से ही वैधता मिलेगी। भागवत ने कहा कि संघ 1925 में स्थापित हुआ था। क्या तब अंग्रेजों से जाकर पंजीकरण कराया जाता? साथ ही स्वतंत्रता के बाद भी भारत के संविधान ने कभी यह अनिवार्य नहीं किया कि हर स्वैच्छिक संगठन सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो तभी वह अस्तित्व में रह सकता है।

असल में कांग्रेस की समस्या संघ के पंजीकरण से नहीं, संघ के प्रभाव से है। जिस संगठन ने बिना सरकारी धन, बिना विदेशी सहायता और बिना सत्ता के सहारे सौ वर्षों तक राष्ट्रजीवन को दिशा दी हो, उससे कांग्रेस की बेचैनी स्वाभाविक है। संघ ने चरित्र निर्माण किया, अनुशासन दिया, समाज को जोड़ा, सेवा का संस्कार दिया और राष्ट्रवाद को जीवन का व्यवहार बनाया। दूसरी ओर कांग्रेस का एक हिस्सा वर्षों तक विदेशी शक्तियों के सामने वैचारिक समर्पण करता रहा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौते करने वाली राजनीति आज संघ से राष्ट्रभक्ति का प्रमाण मांग रही है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है। यह नागरिकों का मौलिक अधिकार है। संविधान कहीं नहीं कहता कि हर सामाजिक संगठन को पहले सरकार के सामने सिर झुकाकर अनुमति लेनी होगी। सोसाइटी कानून, न्यास कानून और अन्य व्यवस्थाएं केवल कानूनी सुविधाओं के लिए हैं, अस्तित्व के लिए नहीं।

संघ के पंजीकरण प्रमाणपत्र को देखने की चाह रखने वाले प्रियांक खरगे, पवन खेड़ा और कांग्रेस के नेताओं को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में मंत्री होना कानून से ऊपर होना नहीं होता। किसी मंत्री की व्यक्तिगत इच्छा कानून नहीं बन जाती। यदि कानून में अनिवार्यता नहीं है, तो

केवल राजनीतिक नफरत के कारण किसी संगठन को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। यही विधि का शासन है, यही संविधान की आत्मा है।

संघ को समझने के लिए उसकी मूल प्रकृति को समझना आवश्यक है। संघ कोई पारंपरिक कार्यालयी संस्था नहीं, बल्कि समाज आधारित आंदोलन है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इसे सदस्यता कार्ड, शुल्क और कागजी ढांचे की बजाय शाखा, संस्कार और स्वयंसेवा के आधार पर खड़ा किया। आज भी कोई व्यक्ति शाखा में जाकर स्वयंसेवक बन सकता है। यही कारण है कि संघ समाज के बीच रहता है, किसी फाइल में बंद नहीं रहता। संघ अपने आरम्भकाल से ही सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ता रहा है। संघ में औपचारिक सदस्यता और कठोर संस्थागत नियंत्रण नहीं होता। शाखाएं अपने संसाधनों से चलती हैं और संगठन का संचालन सामाजिक सहभागिता से होता है।

इतिहास यह भी बताता है कि संघ को बार-बार राजनीतिक दमन का सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगाया गया, आपातकाल में हजारों स्वयंसेवक जेल भेजे गए, बाबरी प्रकरण के बाद भी हमला हुआ। लेकिन हर बार संघ और अधिक मजबूत होकर निकला। इसका कारण यह था कि संघ की जड़ें सत्ता में नहीं, समाज में हैं। मोहन भागवत ने भी याद दिलाया कि सरकारें संघ पर प्रतिबंध लगाती रहीं, इसका अर्थ ही यह है कि सरकारें संघ के अस्तित्व और प्रभाव को मानती रही हैं।

देखा जाये तो संघ विरोधी बार बार पारदर्शिता और कराधान का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन वह जानबूझकर न्यायालयों के निर्णयों को नजरअंदाज करते हैं। "गुरु दक्षिणा" को लेकर न्यायालयों ने पारस्परिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया था। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट माना कि स्वयंसेवकों का स्वैच्छिक योगदान करयोग्य आय नहीं माना जा सकता। संघ ने कभी कानून से छूट नहीं मांगी। उसने केवल वही स्वीकार किया जो कानून कहता है। कानून जहां लागू होता है, वहां संघ के सहयोगी संगठन विधिवत पंजीकृत हैं, लेखा परीक्षण कराते हैं और अपने प्रतिवेदन भी प्रकाशित करते हैं।

यही वह बिंदु है जहां कांग्रेस का पाखंड खुलकर सामने आता है। दशकों तक सत्ता में रहने वाली पार्टी आज संघ से पारदर्शिता मांग रही है, जबकि स्वयं उसके इतिहास पर आपातकाल, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विदेशी प्रभाव के आरोप लगे हुए हैं। जो दल लोकतंत्र को कुचलने के लिए आपातकाल थोप सकता है, वह आज लोकतांत्रिक मूल्यों का उपदेश दे रहा है। यह राजनीतिक हास्य से अधिक कुछ नहीं।

मोहन भागवत ने बिल्कुल सही कहा कि संघ खुलकर काम करता है, किसी गुप्त संगठन की तरह नहीं। लाखों शाखाएं, हजारों सेवा प्रकल्प, शिक्षा, ग्राम विकास, आपदा राहत, सामाजिक समरसता, वनवासी कल्याण, गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण, संघ का हर कार्य समाज के सामने है। यदि संघ में कुछ छिपा होता तो वह सौ वर्षों तक सार्वजनिक जीवन में इतने व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता।

दरअसल संघ की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि उसने राष्ट्रवाद को केवल नारों तक सीमित नहीं रखा। जब भी देश पर संकट आया, स्वयंसेवक सबसे पहले खड़े दिखाई दिए। विभाजन के समय राहत कार्य हो, प्राकृतिक आपदाएं हों, महामारी का दौर हो या सीमा पर सैनिकों के परिवारों की सहायता, संघ के कार्यकर्ता हर जगह सक्रिय रहे। यही कारण है कि भारत का सामान्य नागरिक संघ को कागजी संस्था नहीं, राष्ट्रीय चेतना का प्रहरी मानता है।

संघ को लेकर सबसे अधिक भ्रम उन लोगों में है जो भारत को केवल सत्ता और चुनाव की नजर से देखते हैं। संघ सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए काम करता है। यही कारण है कि वह राजनीतिक उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहता है। मोहन भागवत ने हाल में कहा था कि संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, लेकिन सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला संगठन भी है। यह कथन बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने कभी शाखा देखी ही नहीं, वह संघ पर सबसे अधिक आरोप लगाते हैं।

देखा जाये तो आज आवश्यकता इस बात की है कि संघ को राजनीतिक चश्मे से नहीं, उसके कार्यों से देखा जाए। यदि कोई संगठन बिना सरकारी सहायता के, बिना विदेशी धन के और बिना सत्ता के दबाव के सौ वर्षों तक राष्ट्रसेवा करता है, तो उसकी वैधता किसी सरकारी रजिस्टर से नहीं, जनता के विश्वास से तय होती है।

कांग्रेस और संघ विरोधियों को यह समझ लेना चाहिए कि संघ को डराकर, बदनाम करके या कानूनी भ्रम फैलाकर कमजोर नहीं किया जा सकता। संघ की शक्ति कागजों से नहीं, करोड़ों स्वयंसेवकों के समर्पण से आती है। उसका अस्तित्व किसी मंत्री की कृपा पर नहीं, भारत की सांस्कृतिक आत्मा पर आधारित है। जो सौ वर्षों से राष्ट्र को सब कुछ दे रहा हो, उसे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती। राष्ट्र स्वयं उसका परिचय बन जाता है।

साथ ही संघ को किसी वंशवादी राजनीति से चरित्र प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस संगठन ने सौ वर्षों तक बिना सत्ता, बिना सरकारी संरक्षण और बिना विदेशी सहारे के राष्ट्रजीवन को दिशा दी हो, उसकी पहचान किसी सरकारी मुहर से नहीं होती। संघ का परिचय उसके करोड़ों स्वयंसेवकों की तपस्या है, उसकी शाखाओं का अनुशासन है, उसकी सेवा का विस्तार है और भारत माता के प्रति उसका अखंड समर्पण है। राजनीतिक दल सत्ता से बनते और मिट जाते हैं, लेकिन संघ जैसी राष्ट्रशक्ति पीढ़ियों तक समाज की चेतना में जीवित रहती है। संघ को मिटाने के सपने देखने वाले आते जाते रहे, लेकिन संघ आज भी उतना ही दृढ़, उतना ही प्रभावशाली और उतना ही राष्ट्रनिष्ठ खड़ा है, क्योंकि उसका आधार सत्ता नहीं, भारत की सनातन आत्मा है।

बहरहाल, जिस संगठन के स्वयंसेवक प्रतिदिन यही मंत्र जपते हों, "तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें ना रहें", उससे अपना पंजीकरण कराने को कहना कांग्रेस नेताओं की राजनीतिक हताशा ही नहीं, बल्कि उनकी बेवकूफी भी प्रदर्शित करता है।

सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण मामला, जेसीबी और भारी पुलिस बल की तैनाती से बढ़ी हलचल, 14 जुलाई को सुनवाई

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। मेरठ के सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में संभावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई की आहट से शनिवार को माहौल गरमा गया। आवास एवं विकास परिषद द्वारा जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस बल को बुलाए जाने के बाद क्षेत्र में गहमागहमी बढ़ गई। कार्रवाई की आशंका से स्थानीय लोगों और व्यापारियों में बेचैनी का माहौल देखने को मिला।

जेसीबी और फोर्स पहुंचने से बढ़ी हलचल

शनिवार को परिषद कार्यालय के बाहर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। क्षेत्र में जेसीबी मशीनों और पुलिस बल की मौजूदगी से ध्वस्तीकरण की चर्चाएं तेज हो गईं। संभावित कार्रवाई की खबर फैलते ही प्रभावित परिवारों और व्यापारियों में चिंता बढ़ गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। अधिकारियों की गतिविधियों पर स्थानीय लोग लगातार नजर बनाए रहे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा है मामला

जानकारी के अनुसार सेंट्रल मार्केट के आवासीय भवनों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आवासीय परिसरों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण संबंधी आदेश दिए थे। इसके बाद से आवास विकास परिषद और प्रशासन न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को लेकर प्रक्रिया में जुटे हुए हैं।

14 जुलाई को होनी है अगली सुनवाई

मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को प्रस्तावित है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से किसी बड़े ध्वस्तीकरण अभियान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन परिषद कार्यालय के बाहर बढ़ी गतिविधियों ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। प्रभावित लोगों का कहना है कि वे मामले के समाधान की उम्मीद लगाए हुए हैं, जबकि अधिकारी न्यायालय के आदेशों के अनुरूप आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटे हैं।

लोगों में बना हुआ है संशय

क्षेत्र में रहने वाले परिवारों और व्यापारियों के बीच पूरे घटनाक्रम को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि सुनवाई से पहले किसी भी कार्रवाई की आशंका उन्हें परेशान कर रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सभी कदम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही उठाए जाएंगे।

सुरजीत ने राहुल गाँधी से की मुलाकात, चुनाव में अवसर के संकेत

आर्यावर्त संवाददाता

कूरेभार/सुलतानपुर। विकास खंड कूरेभार के रूसहा मठिया गांव निवासी व विधान सभा सुलतानपुर के सुरजीत कुमार ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा सांसद, राहुल गांधी जी से दिल्ली उनके आवास पर आत्मीय एवं शिष्टाचार मुलाकात की। जिसमें उन्हें विधानसभा 191 कादीपुर से चुनाव लड़ने का अवसर मिल सकता है। बताते चले सुरजीत कुमार 9 अक्टूबर 2021 बहुजन समाज पार्टी छोड़ कर अपने सेकडों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। बताया जा रहा कि इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक विभिन्न पदों पर रहकर पार्टी के लिए काफी अर्से से काम किया था। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा तक चुनाव लड़वाने में पार्टी के प्रति इनका काफी योगदान रहा है

कानपुर की ऐतिहासिक पहचान संकट में, लाल इमली मिल के क्लॉक टावर से 105 साल पुरानी सुइयां गायब, क्या ढूंढ पाएगी पुलिस?

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। यूपी के कानपुर जिले का लाल इमली मिल का ऐतिहासिक क्लॉक टावर इन दिनों रहस्यमयी तरीके से घड़ियों की सुइयां गायब होने के कारण चर्चा में है। 105 वर्ष पुराने इस क्लॉक टावर की तीन घड़ियों से सुइयां गायब होने के बाद मिल प्रबंधन और पुलिस दोनों के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। खास बात यह है कि जिस टावर से सुइयां गायब हुई हैं, उसकी ऊंचाई करीब 128 फीट है और वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी ऊंचाई वाले टावर से चोरी कैसे हुई।

मिल प्रबंधन के अनुसार 5 जून को सबसे पहले एक घड़ी की सुइयां गायब मिली थीं। उस समय इसे आंधी-तूफान का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन 18 जून को दो अन्य घड़ियों की सुइयां भी गायब हो गईं। इसके बाद चोरी की आशंका गहराने पर मिल प्रबंधक सुनील कुमार मिश्र ने कर्नलगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई।

कैसे होगी जांच? नहीं मिली टावर की चाबी

मामले की जांच के लिए पुलिस टीम लाल इमली परिसर पहुंची और सुरक्षा कर्मियों व कर्मचारियों से पूछताछ की। जांच के दौरान एक बड़ी समस्या सामने आई कि जिस क्लॉक टावर की जांच की जानी है, उसकी छत तक जाने वाली सीढ़ियों का दरवाजा पिछले 6 वर्षों से बंद पड़ा है और उसकी चाबी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पुलिस अभी तक टावर के शीर्ष तक नहीं पहुंच सकी है। अब चाबी नहीं मिलने की स्थिति में ताला तोड़कर जांच आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

कानपुर की पहचान हैं ये घड़ियां

बताया जा रहा है कि साल 1911 से 1921 के बीच बने इस ऐतिहासिक घंटाघर की घड़ियां कभी कानपुर की पहचान मानी जाती थीं। पहले एक विशेष टीम नियमित रूप से टावर पर जाकर घड़ियों के यांत्रिक तंत्र में चाबी भरती थी, जिससे चारों घड़ियां लगातार चलती थीं, लेकिन 2013 में मिल बंद होने और कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद यह व्यवस्था भी समाप्त हो गई।

मंत्रालय ने तलब की रिपोर्ट

सूत्रों के मुताबिक मामले को गंभीरता से लेते हुए वस्त्र मंत्रालय ने भी रिपोर्ट तलब की है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि सुइयां वास्तव में चोरी हुई हैं या फिर किसी अन्य कारण से गायब हुई हैं। ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ा यह रहस्य अब कानपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

हुसैन के साथ एक ईसाई वहेब कलबी ने भी शहादत पेशकी

सुलतानपुर। चार मोहर्रम को हुसैनिया तुराबखानी में मौलाना सैयद अतहर अब्बास मुजफ्फरनगर ने पढ़ा कि कर्बला के मैदान में जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से यजीदी फौज ने घेर लिया था तो उसी रास्ते से एक ईसाई जिसका नाम वहेब कलबी था वह शादी करके मां बीवी को साथ लेकर कर्बला के उसी रास्ते से गुजरा जहां पर हुसैन ठहरे हुए थे वहेब की मां ने हुसैन से पूछा आप कौन हैं कहां के रहने हुसैन ने कहा मैं रसूले ख़ुदा का नेवासा हुसैन हूं मुझ से मेरा वतन छोड़ा या गया है इतनी बड़ी फौज मुझे कत्ल करने पर आमादा है वहेब की मां ने बेटे को हुसैन के हवाले किया और मैदान में हुसैन की तरफ से शहादत पेश करने के लिए भेजा वहेब मैदान में आया जंग करते करते जब गिर पड़ा तो जालिमों ने सर काट कर मां की तरफ भेजा मां ने सर उठाकर फिर यजीदी फौज की तरफ भेजा और कहा हम जो राहें खुदा में कुर्बान कर देते हैं।

मौत से पहले बांध लिए थे हाथ! फिरोजाबाद में नहर में मिले प्रेमी-प्रेमिका के शव, मचा कोहराम

आर्यावर्त संवाददाता

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां नगला प्रभु के पास नहर में एक प्रेमी और प्रेमिका का शव उतराता हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने पानी में शव देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को नहर से बाहर निकलवाया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक, दोनों शवों की हालत देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर थी कि युवक और महिला के हाथ एक ही दुपट्टे से बंधे हुए थे। इस दृश्य के बाद पूरे क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। पुलिस ने मौके पर जांच शुरू की और दोनों की पहचान के प्रयास किए। पुलिस को तलाशी के दौरान मिले दस्तावेज और मोबाइल फोन से युवक की पहचान एटा जिले के आवागढ़ थाना क्षेत्र के

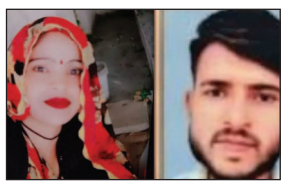

सहनवा गांव निवासी जितेंद्र लोधी उर्फ जीतू के रूप में हुई। वहीं मृत महिला की पहचान जसराना क्षेत्र के नगला फकीरा गांव निवासी फूलनदेवी के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि फूलनदेवी शादीशुदा थी। उसका पति ट्रक चालक है और घटना के समय घर से बाहर था। जैसे ही महिला और युवक की मौत की खबर परिजनों तक पहुंची, परिवारों में कोहराम मच गया। दोनों परिवारों के लोग मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर स्तब्ध रह गए। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि जितेंद्र 17 जून की सुबह घर से काम के सिलसिले में बाहर जाने की बात कहकर निकला था। इसके बाद उसकी परिजनों से फोन पर बातचीत होती रही, लेकिन शाम के बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच नहर में शव मिलने की सूचना ने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस फिलहाल इस मामले को कई एंगल से जांच रही है। प्रारंभिक तौर पर मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। दोनों के हाथ एक ही दुपट्टे से बंधे मिलने के कारण पुलिस आत्महत्या की आशंका से भी जांच कर रही है। हालांकि अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि दोनों के बीच किस तरह का संबंध था और घटना से पहले दोनों कहां थे। दोनों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल, लोकेशन और आपसी संपर्कों की जांच की जा रही है ताकि घटना की पूरी कड़ी को जोड़ा जा सके। सीओ शिकोहाबाद अमरीश कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

शिवसेना ने स्थापना दिवस पर संगठन के उद्देश्यों और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर रखे विचार

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। शिवसेना उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में संगठन की स्थापना के उद्देश्य, सामाजिक सरोकारों और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर अपने विचार व्यक्त किए गए। विज्ञप्ति के अनुसार शिवसेना की स्थापना 19 जून 1966 को स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे द्वारा भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा सामाजिक हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। विज्ञप्ति में कहा गया कि संगठन का मूल उद्देश्य सामाजिक हितों को राजनीतिक मंच पर उठाना और समाज के वंचित व पीड़ित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए कार्य करना रहा है। संगठन ने दावा किया कि देश में समय-समय पर जाति, धर्म और विभिन्न राजनीतिक समीकरणों के आधार पर चुनावी राजनीति होती रही है, लेकिन शिवसेना सामाजिक न्याय

और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देती रही है। शिवसेना ने अपने वक्तव्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि संगठन स्वयं को समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के साथ खड़ा मानता है। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि सामाजिक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संगठन निरंतर संघर्ष करता रहेगा। संगठन ने अपने विचार रखते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का उल्लेख किया तथा कहा कि शिवसेना समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को सर्वोपरि मानकर कार्य करने का संकल्प रखती है। साथ ही यह भी कहा गया कि चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद संगठन अपने उद्देश्यों से पीछे नहीं हटेगा। वर्तमान राष्ट्रीय और वैश्विक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए विज्ञप्ति में आर्थिक चुनौतियों और राजनीतिक विमर्श पर भी टिप्पणी की गई। संगठन ने कहा कि देश को सही दिशा देने के लिए राजनीतिक दलों को केवल राजनीतिक रणनीति तक सीमित न रहकर व्यापक सामाजिक दायित्वों को भी समझना चाहिए। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आयोजित कार्यक्रम में शिवसेना के जिलाध्यक्ष अजय कांत त्रिपाठी सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें सचिव बृजेश वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष संदीप तिवारी और सोनू सिंह के नाम भी शामिल बताए गए।

खेत में मिला अज्ञात युवक का शव

जौनपुर। सुरेरी थाना क्षेत्र के पूरेदयाल सोरहा गांव कै खेत में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। शव मिलने की सूचना से ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। गांव का एक युवक भैंस चरा रहा था, तभी उसकी नजर खेत में पड़े शव पर पड़ी। उसने तत्काल इसकी सूचना ग्रामीणों और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया पुलिस जांच के दौरान मृतक के हाथ पर प्रीति महाकाल लिखा हुआ पाया गया, जिसे पहचान का महत्वपूर्ण सुराग माना जा रहा है। युवक की पहचान नहीं हो सकी थी।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

अब नहीं होगी नीट में चूक! नोएडा के 23 केंद्रों पर सख्त पहरा, पार्किंग से लेकर ट्रैफिक तक खास इंतजाम, 11000 छात्र देंगे परीक्षा

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक विवाद के बाद अब दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर नोएडा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। रविवार को जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी री-एग्जाम कराया जाएगा, जिसमें करीब 11,302 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पिछली परीक्षा में सामने आई गड़बड़ियों को देखते हुए इस बार प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत किया है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित इस परीक्षा के लिए इस बार विशेष सावधानी बरती जा रही है। प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि इस बार किसी भी निजी स्कूल को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। सभी केंद्रों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे, जो परीक्षा की हर गतिविधि पर नजर

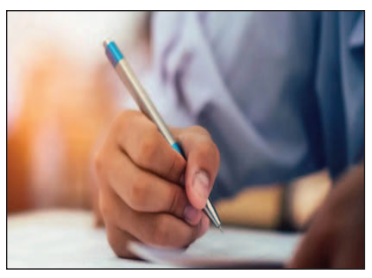

रखेंगे। प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र की सही जानकारी के लिए नया एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लें। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश का अंतिम समय दोपहर 1:30 बजे निर्धारित किया गया है। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए जैमर भी लगाए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर सख्त व्यवस्था की गई है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि अभ्यर्थियों को शांत और सुरक्षित माहौल मिले, जिससे वे बिना किसी परेशानी के परीक्षा दे सकें।

23 केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

नोएडा डीसीपी हेडक्वार्टर के अनुसार जिले में नीट यूजी री-एग्जाम के लिए कुल 23 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को जाम की समस्या से बचाने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। जिन स्थानों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहां से करीब 200 मीटर के आसपास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बस डिपो जैसे प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसका उद्देश्य दूर-दराज से आने वाले अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद करना है। पुलिस ने साफ किया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हर परीक्षा केंद्र के बाहर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। केंद्रों के आसपास सुरक्षा घेरा बनाया गया है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हो सके। प्रशासन का कहना है कि पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार सुरक्षा के हर स्तर पर विशेष ध्यान दिया गया है।

दिल्ली जैसा हेल्थ हब ताज नगरी में... ग्रेटर आगरा योजना में 60 हेक्टेयर में विकसित होगी मेडिसिटी, मिलेंगी ये खास सुविधाएं

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। ताज नगरी आगरा जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई पहचान बनाने जा रही है। अब तक बेहतर इलाज के लिए दिल्ली और एनसीआर का रुख करने वाले मरीजों को भविष्य में अपने ही क्षेत्र में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। आगरा विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी ग्रेटर आगरा आवासीय योजना के तहत 60 हेक्टेयर क्षेत्र में विशाल मेडिसिटी विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है।

यह मेडिसिटी केवल आगरा ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा केंद्र बनेगी। यहां सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, आधुनिक मेडिकल क्लीनिक, हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर और विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सा संस्थान स्थापित किए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे लाखों लोगों को गंभीर

बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली या अन्य महानगरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

बनाई जाएंगी 10 आधुनिक टाउनशिप

ग्रेटर आगरा योजना लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले इनर रिंग रोड के पास एत्मादपुर क्षेत्र के रहनकला और रायपुर गांवों में विकसित की जा रही है। करीब 449 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित इस मेगा प्रोजेक्ट में 10 आधुनिक टाउनशिप बसाई जाएंगी, जहां आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का समन्वित विकास होगा।

कहां बसेगी मेडिसिटी?

एडीए के मुख्य अभियंता संजीव कुमार के अनुसार योजना के विस्तार के लिए एत्मादपुर मदरा क्षेत्र में 124 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसी भूमि में 60 हेक्टेयर क्षेत्र मेडिसिटी के लिए आरक्षित किया गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और किसानों को मुआवजा देने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

मेडिसिटी में होंगे देश के बड़े अस्पताल

मेडिसिटी में देश के प्रतिष्ठित व बड़े अस्पताल ग्रुपों को आमंत्रित करने की योजना है। यहां हृदय रोग, कैंसर, न्यूरोलॉजी, ट्रॉमा केयर और अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार की विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस और आसपास के जिलों के मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

कब से शुरू होगी बुकिंग?

दो दिन पहले योजना की प्रगति का जायजा लेने पहुंचे प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद ने भी परियोजना की समीक्षा की थी। एडीए अधिकारियों के मुताबिक जुलाई माह से ग्रेटर आगरा योजना के लिए बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यदि योजना तय समय पर पूरी हुई तो आगरा न सिर्फ पर्यटन बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी उत्तर भारत का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।

योजनाओं से लाभान्वित लोग किये गये सम्मानित

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। नगर के टाउन हॉल मैदान में आयोजित स्वनिधि महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सदस्य विधान परिषद बृजेश सिंह "प्रिंसू" ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने रेहड़ी-पटरी और छोटे व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने कहा कि बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराकर सरकार छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने लाभार्थियों से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। आगे कहा कि तीस हजार तक का क्रेडिट कार्ड निशुल्क स्ट्रीट वेंडर को दिया जा रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत

प्रजापति ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। अध्यक्षता करते हुए नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष मनोरमा मौर्या ने कहा कि नगर क्षेत्र के पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पालिका लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वनिधि योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों को आर्थिक संबल मिला है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। संचालन सलमान शेख ने किया। कर अधीक्षक अंजू राय, शहर मिशन प्रवन्धक-जितेन्द्र सिंह, सभासद राहुल साहू, संदीप चौधरी सामुदायिक आयोजन, राजस्व निर्धारण अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद, यूनियन बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि गण सहित आदि लोग मौजूद रहे।

ऑनलाइन हैंडबैग खरीदने जा रही हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

हैंडबैग की सामग्री भी बहुत अहम होती है। चमड़ा, कैनवास, नायलॉन आदि अलग-अलग सामग्रियों में उपलब्ध होते हैं। चमड़े के बैग्स लंबे समय तक चलते हैं और स्टाइलिश दिखते हैं

हैंडबैग एक ऐसा फैशन का सामान है, जो न केवल महिलाओं की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि उनके लुक को भी खास बनाता है। जब आप ऑनलाइन हैंडबैग खरीदने जा रही हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपका चयन सही हो और आपको संतुष्टि मिले। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप ऑनलाइन हैंडबैग का सही चयन कर सकती हैं।

सही आकार चुनें

जब आप ऑनलाइन हैंडबैग खरीदें तो सबसे पहले उसके आकार पर ध्यान दें। यह तय करें कि आपको छोटे, मध्यम या बड़े आकार का बैग चाहिए। छोटे आकार के बैग रोजमर्रा के उपयोग के लिए बेहतर होते हैं, जबकि बड़े आकार के बैग यात्रा या शॉपिंग के लिए उपयुक्त होते हैं। मध्यम आकार के बैग्स ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए अच्छे होते हैं। इस तरह आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही आकार चुन सकती हैं।

सामग्री का चयन करें

हैंडबैग की सामग्री भी बहुत अहम होती है। चमड़ा, कैनवास, नायलॉन आदि अलग-अलग सामग्रियों में उपलब्ध होते हैं। चमड़े के बैग्स लंबे समय तक चलते हैं और स्टाइलिश दिखते हैं, लेकिन इनकी देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। कैनवास बैग्स हल्के होते हैं और आसानी से साफ किए जा सकते हैं, जबकि नायलॉन पानी से बचाने वाले होते हैं और बारिश में भी सुरक्षित रहते हैं। अपनी जरूरतों और पसंद के अनुसार सही सामग्री का चयन करें।

रंगों का मेल देखें

आपका हैंडबैग आपके कपड़ों के साथ मेल खाना चाहिए ताकि आपका लुक पूरा लगे। अगर आप रोजमर्रा की पोशाक पहनती हैं तो काले, भूरे या बेज रंग के बैग्स अच्छे रहते हैं क्योंकि ये लगभग सभी रंगों के साथ जाते हैं, वहीं अगर आप पार्टी के लिए तैयार होती हैं तो चमकीले रंग जैसे लाल, नीला या हरा रंग का बैग चुन सकती हैं जो आपके लुक को और भी खास बनाएंगे।

स्टाइल पर ध्यान दें

स्टाइल भी बहुत जरूरी होता है जब बात फैशन की आती है। फ्लैप बंद, जिपर बंद या मैग्नेटिक बंद जैसे अलग-अलग स्टाइल उपलब्ध होते हैं। फ्लैप बंद बैग्स क्लासिक लुक देते हैं जबकि जिपर बंद बैग्स आधुनिक दिखते हैं। मैग्नेटिक बंद बैग्स जल्दी खोलने बंद करने में आसान होते हैं। अपने स्टाइल और सुविधा के अनुसार सही बंद स्टाइल चुनें ताकि आपका हैंड बैग न केवल उपयोगी हो बल्कि आपकी व्यक्तिगत शैली को भी दर्शाए।

ग्राहक समीक्षा पढ़ें

ऑनलाइन खरीदारी करते समय ग्राहक समीक्षा पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपको उत्पाद की गुणवत्ता और प्रदर्शन का सही अंदाजा हो सके। अच्छी रेटिंग वाले उत्पादों को प्राथमिकता दें और नकारात्मक समीक्षाओं पर ध्यान दें ताकि किसी भी तरह की निराशा से बचा जा सके। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप आसानी से अपने लिए सबसे अच्छा हैंड बैग चुन सकती हैं जो आपकी जरूरतों और पसंद के हिसाब से फिट बैठेगा।

व्रत में ट्रैवल करना है तो साथ लेकर जाएं ये फूड्स, नहीं होगी थकान-कमजोरी

भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ नवरात्रि के दौरान मां आदिशक्ति दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। इस दौरान ज्यादातर लोग व्रत भी करते हैं। हालांकि कम ही ऐसा होता है कि लोग नवरात्रि में कहीं जाएं, लेकिन अगर आपको किसी वजह से ट्रेवल करना पड़ रहा है तो सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि व्रत में बाहर का खाया नहीं जा सकता है और पूरी तरह से खाली पेट ट्रैवलिंग करने की वजह से काफी थकान और कमजोरी हो सकती है। खाली पेट ट्रेवल करने की वजह से कुछ लोगों का जी भी मिचलाने लगता है। ऐसे में ट्रैवल करते वक्त अपने साथ आप कुछ ऐसे फूड्स पैक कर सकते हैं जो व्रत में खाए जा सकते हैं और लंबे समय तक खराब भी नहीं होते हैं।

शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शुरू हो चुकी हैं। 11 अक्टूबर 2024, शुक्रवार को महानवमी सेलिब्रेट की जाएगी और नवरात्रि का समापन हो जाएगा। अगर आपने भी नवरात्रि के व्रत रखे हैं और किसी वजह से ट्रेवल करना पड़ रहा है तो जान लें कि आपको अपने साथ कौन से फूड्स पैक करने चाहिए जो आपको व्रत में एनर्जी देंगे और थकान, कमजोरी से बचाव होगा।

नट्स और सीड्स रखें साथ

एनर्जी बनाए रखने के लिए नट्स एक बेहतरीन विकल्प है। बादाम, काजू, पिस्ता, ऐसे नट्स हैं, जिनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, जिससे थकावट और कमजोरी महसूस नहीं होती है। चाहे तो पंपकिन सीड्स, सूरजमुखी की बीज, आदि का मिक्सर भी साथ में रख सकते हैं। ये गुड मिक्स आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद रहता है और खराब होने का डर भी नहीं रहता है।

फलों को रखें साथ

व्रत में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ सेब, कीवी और नाशपाती जैसे फल रखें। ये तीनों ही फल आपकी एनर्जी बूस्ट करेंगे और जल्दी खराब भी नहीं होते हैं साथ ही में पेट भी भरा हुआ महसूस होता है। ये फल न्यूट्रिएंट्स से भरपूर भी होते हैं, इसलिए सेहत के लिए काफी फायदेमंद रहते हैं।

कुट्टू के आटे की पूरी

अगर ट्रेवलिंग में ही शाम के समय का फलाहार करना हो तो आप अपने साथ कुट्टू के आटे की पूरी भी पैक कर सकते हैं। ये कम से कम 6 से 7 घंटे तक खराब नहीं होती है। अगर आप ज्यादा ऑयली नहीं खाते हैं तो पूरी की बजाय पराठे बना सकते हैं और साथ में हरी चटनी पैक कर लें।

फलाहारी ढोकला

व्रत के दौरान ट्रेवल कर रहे हैं तो आप अपने साथ फलाहारी ढोकला पैक कर सकते हैं। ये लाइट भी रहेगा जिससे सफर के दौरान आपको पाचन से जुड़ी कोई परेशानी होने की संभावना नहीं रहेगी। बेसन और सूजी का ढोकला तो ज्यादातर लोग बनाते हैं आप व्रत के लिए सिंघाड़े के आटे का ढोकला बनाकर पैक कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि पहले से ही हल्के मसाले ढोकला के बैटर में डाल दें। इसमें तड़का न लगाएं, नहीं तो पानी की वजह से ये खराब हो सकता है। साथ में धनिया की चटनी पैक कर लें।

ऑनलाइन फूड के डिब्बों से कैंसर का खतरा! जानें इसके पीछे का लॉजिक

ऑनलाइन फूड्स को जिन डिब्बों में डिलीवर किया जाता है ये हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इनसे कैंसर तक का खतरा रहता है। मिनटों में घर पहुंच जाने वाले फूड्स के डिब्बे किस कदर हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है चलिए आपको बताते हैं।

ऑनलाइन फूड की आदत लोगों को इस कदर पड़ गई है कि वे घरों में खाना बनाने से बचते हैं। बच्चा हो या बड़ा... हर किसी को मिनटों में घर पहुंच जाने वाले फूड्स की लत लग गई है। ये हमारे बिगड़े हुए लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है जो शरीर को बीमारियों का घर बना रहा है। जोमैटो, स्विगी के अलावा दूसरे ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म के जरिए खाने पीने की चीजों को काले और सफेद डिब्बे में भी डिलीवर किया जाता है। इन डिब्बों से भी हमें गंभीर बीमारियों के होने का डर बना रहता है। दरअसल, प्लास्टिक में गर्म खाना डालने से इसमें केमिकल रिलीज होता है जो हमारे शरीर में जाकर गंभीर नुकसान पहुंचाता है।

कहा जाता है कि ये खाना जितना ज्यादा गर्म होगा इससे हमारे स्वास्थ्य को उतना ही नुकसान होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लास्टिक में मौजूद बीपिए खाने में मिलता है। इस वजह से खाने की चीजों में ही एंडोक्राइन डिस्ट्रक्टिंग जहर बनता है। चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर इसके पीछे का पूरा लॉजिक क्या है और आप किस तरह बचाव कर सकते हैं।

प्लास्टिक से निकलते हैं कई रसायन

आज ये असंभव है कि हम अपनी लाइफ से प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म कर दें। अब मुद्दा ये है कि हम इसके इस्तेमाल को कितना कम कर सकते हैं। सबसे पहले, हमें यह समझना होगा कि प्लास्टिक इतनी खतरनाक क्यों है। FDA ने माना है कि गर्म होने पर प्लास्टिक से 55 से 60 अलग-अलग रसायन निकलते हैं। इसलिए, जब आप प्लास्टिक को गर्म करते हैं चाहे वह आपके माइक्रोवेव में प्लास्टिक के कंटेनर में खाना गर्म करना हो या प्लास्टिक की प्लेट या कंटेनर में गर्म खाना डालना हो तो वह गर्मी उसी भोजन में रसायन छोड़ना शुरू कर देती है जिसे आप खाने वाले हैं। ये विषाक्त पदार्थ और रसायन एस्ट्रोजन और कई अन्य हार्मोन की नकल करते हैं, जिससे हार्मोनल असंतुलन होता है।

इसके परिणामस्वरूप पीसीओडी, डिम्बग्रंथि संबंधी समस्याएं, स्तन कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और बहुत कुछ जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। यही कारण है कि कुछ कैंसर के उपचार में हार्मोन थेरेपी शामिल होती है। जब आप जीवनशैली या पारंपरिक उपचारों के कारण हार्मोनल असंतुलन का सामना करते हैं तो आप हार्मोन थेरेपी करवाते हैं। इसलिए उस स्तर पर भी यह समझा जाता है कि आपके हार्मोन को संतुलित रखना महत्वपूर्ण है। हालांकि रिसर्च और एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग में भोजन की डिलीवरी को बंद करने का आग्रह किया जा रहा है। इसके पीछे कई स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं।

एक रिसर्च में पाया गया है कि प्लास्टिक पैकेट्स में 143 रासायनिक पदार्थ मौजूद हैं जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा का गजया कार्डबोर्ड पैकेट्स में भी 89 कैंसर कारी रसायन पाए गए हैं। यह अध्ययन "Frontiersin Toxicology" जर्नल में प्रकाशित हुआ है जिसमें बताया गया है कि इन रसायनों में से कई न केवल कैंसर बल्कि इनफर्टिलिटी और जेनेटिक म्यूटेशन का कारण भी बन सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भी खाद्य सामग्री की पैकेजिंग में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश दुकानदारों को प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आपको याद होगा हाल ही में जोमैटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के सीईओ ने भी इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया है।

इस तरह से इसे करें इग्नोर

अगर आप इन डिब्बों से होने वाले नुकसान से खुद को बचा सकते हैं तो आपको पॉलीप्रोपाइलीन से बने प्लास्टिक का यूज करना चाहिए। इस मटेरियल नेस स्ट्रा और बोतल के ढक्कन बनाए जाते हैं। इसमें केमिकल रेजिस्टेंस होता है जो किसी भी तरह के एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। वैसे आप प्लास्टिक कंटेनर की जगह कांच, स्टील, नेचुरल फाइबर क्लॉथ, बैंबू, लकड़ी और पेपर का यूज कर सकते हैं।

टैक्सपेयर्स अलर्ट! आईटीआर फॉर्म में हुए बड़े बदलाव

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म में कई अहम बदलाव किए गए हैं। अब कैपिटल गेन, F&O ट्रेडिंग, बैंक बैलेंस और टैक्स छूट से जुड़ी ज्यादा जानकारी देनी होगी। गलत जानकारी या डेटा में अंतर होने पर नोटिस मिलने का जोखिम बढ़ सकता है।

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वाले करदाताओं को इस बार फॉर्म में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। कैपिटल गेन, शेयर ट्रेडिंग, बैंक बैलेंस और टैक्स छूट से जुड़ी ज्यादा जानकारी अब देनी होगी। सरकार ने इन बदलावों को टैक्स विभाग की डेटा आधारित जांच प्रणाली के अनुरूप तैयार किया है।

टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार अब Annual Information Statement (AIS), TDS रिकॉर्ड, ब्रोकरेज रिपोर्ट और अन्य स्रोतों से मिले डेटा का मिलान कर रही है। ऐसे में रिटर्न भरते समय छोटी गलती या जानकारी में अंतर भी नोटिस या जांच का कारण बन सकता है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रेया गुप्ता गोयल के मुताबिक, अब रिटर्न फाइलिंग को केवल औपचारिक प्रक्रिया समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। टैक्स विभाग के पास उपलब्ध जानकारी और रिटर्न में दी गई जानकारी का मेल होना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है।

आईटीआर -1 (सहज) में क्या बदला?

अब दो मकानों तक की आय वाले लोग भी ITR-1 भर सकेंगे। पहले एक से ज्यादा मकान होने पर ITR-2 भरना पड़ता था।

सूचीबद्ध शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड से धारा 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ITR-1 में दिखाया जा सकेगा।

सेकेंडरी पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की नई जानकारी देनी होगी।

विदेश से पेंशन पाने वालों को अब विदेशी पेंशन खाते की जानकारी नहीं देनी होगी।

आईटीआर -2 में क्या नया है?

कैपिटल गेन से जुड़े लेनदेन की अधिक विस्तृत जानकारी देनी होगी।

शेयर बायबैक से हुए नुकसान की अलग से रिपोर्टिंग करनी होगी।

विदेशी संपत्ति, विदेशी बैंक खाते, विदेशी शेयर या विदेश से होने वाली आय की जानकारी देना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा।

अतिरिक्त संपर्क विवरण देने का विकल्प जोड़ा गया है।

आईटीआर -3 में बड़े बदलाव

फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O), इंट्राडे ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग और करेंसी ट्रेडिंग की अलग-अलग जानकारी देनी होगी।

ऑडिटर से संबंधित कुछ रिपोर्टिंग नियम सरल किए गए हैं।

व्यापार और बड़े वित्तीय लेनदेन से जुड़ी अधिक जानकारी मांगी जाएगी।

वैकल्पिक पता, मोबाइल और ईमेल देने की सुविधा जोड़ी गई है।

आईटीआर -4 (सुगम) में क्या बदला?

अनुमानित कराधान योजना अपनाने वाले करदाता अब दो मकानों तक की आय ITR-4 में दिखा सकेंगे।

धारा 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक का LTCG भी रिपोर्ट किया जा सकेगा।

31 मार्च 2026 तक बैंक खाते में मौजूद बैलेंस बताना अनिवार्य कर दिया गया है।

विदेशी पेंशन खाते का विवरण देने की बाध्यता खत्म कर दी गई है।

राजनीतिक चंदे पर नई रिपोर्टिंग

एस.के. पाटोदिया एलएलपी के एसोसिएट डायरेक्टर मिहिर तन्ना के अनुसार, राजनीतिक दलों को दिए गए दान पर 100% टैक्स छूट का दावा करने वाले कई लोगों को हाल में नोटिस मिले हैं। इसलिए अब ITR में संबंधित राजनीतिक दल का PAN नंबर भरने के लिए नया कॉलम जोड़ा गया है।

आईटीआर भरने की आखिरी तारीख

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रहेगी। वहीं, गैर-ऑडिट बिजनेस मामलों और कुछ ट्रस्टों के लिए समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। F&O ट्रेडिंग से आय कमाने वालों को भी 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करने का समय मिलेगा क्योंकि इसे व्यवसायिक आय माना जाता है।

इसके अलावा संशोधित (Revised) रिटर्न दाखिल करने की अवधि भी बढ़ाई गई है। जनवरी 2027 से मार्च 2027 के बीच संशोधित रिटर्न जमा किया जा सकेगा। इसके लिए 5 लाख रुपये तक की आय वालों को 1,000 रुपये और इससे अधिक आय वालों को 5,000 रुपये तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अब यह मान लेना गलत होगा कि रिटर्न में कोई आय नहीं दिखाई गई तो टैक्स विभाग को पता नहीं चलेगा। विभाग को बैंक, म्यूचुअल फंड, ब्रोकर, नियोक्ता और अन्य संस्थाओं से सीधे जानकारी मिलती है। इसलिए रिटर्न जमा करने से पहले सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच जरूर कर लें।

ईपीएफ खाते में नॉमिनी बदलना हुआ आसान! 16 अंकों की वीआईडी से मिनटों में पूरा होगा काम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को EPF खाते में नॉमिनी जोड़ने या बदलने की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से देता है। सही नॉमिनेशन होने से खाताधारक की मृत्यु होने पर जमा राशि और अन्य लाभ परिवार तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ऐसे में EPFO समय-समय पर सदस्यों को अपनी नॉमिनेशन जानकारी अपडेट रखने की सलाह देता है।

ऑनलाइन नॉमिनेशन

ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा केवल उन सदस्यों के लिए उपलब्ध है जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार से सत्यापित है। सदस्य EPFO पोर्टल पर लॉगिन करके नॉमिनी की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी करने के लिए e-Sign करना अनिवार्य है। इसके तहत आधार नंबर दर्ज करना होता है और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के जरिए आवेदन को सत्यापित किया जाता है। वहीं, ऑफलाइन नॉमिनेशन के लिए सदस्य को फॉर्म नंबर-2 भरकर EPFO कार्यालय में जमा करना होता है। इस फॉर्म में EPF, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) से संबंधित जानकारी दर्ज की जाती है।

e-Nomination के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत?

ऑनलाइन नॉमिनेशन करते समय सदस्य को नॉमिनी का नाम, आधार नंबर, जन्म तिथि, लिंग, पता और संबंध जैसी जानकारी देनी होती है। इसके अलावा नॉमिनी की फोटो भी अपलोड करनी होती है, जिसका आकार 100KB से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि लाभार्थी नाबालिग है तो उसके अभिभावक की जानकारी भी देनी होगी। सदस्य बैंक खाते की जानकारी भी दर्ज कर सकते हैं, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। एक से अधिक नॉमिनी होने की स्थिति में सभी को दिए गए हिस्सों का कुल प्रतिशत 100% होना चाहिए।

Virtual ID (VID) ऐसे करें जनरेट

EPFO के e-Sign प्रोसेस में सदस्य आधार नंबर के अलावा UIDAI की 16 अंकों वाली Virtual ID (VID) का भी उपयोग कर सकते हैं। VID बनाने के लिए सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट पर जाएं। वहां Aadhaar Services सेक्शन में "Virtual ID Generator" विकल्प चुनें। इसके बाद अपना 12 अंकों का आधार नंबर और कैप्चा भरकर OTP प्राप्त करें। OTP सत्यापित करने के बाद नई VID जनरेट की जा सकती है या पहले से बनी VID को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। नई VID बनने पर पुरानी VID स्वतः निष्क्रिय हो जाती है।

कब अपडेट करनी चाहिए नॉमिनेशन?

EPFO के अनुसार शादी, बच्चे के जन्म, तलाक या नामित व्यक्ति की मृत्यु जैसी परिस्थितियों में नॉमिनेशन को अपडेट करना जरूरी है। इससे भविष्य में दावों के निपटान में किसी तरह की परेशानी नहीं होती और परिवार को समय पर वित्तीय सहायता मिल जाती है।

नियमों के मुताबिक विवाहित सदस्य के लिए पति या पत्नी को नॉमिनी बनाना अनिवार्य है। वहीं अविवाहित सदस्य, जिनके पति/पत्नी या बच्चे नहीं हैं, वे अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं। EPFO का मानना है कि समय पर अपडेट की गई नॉमिनेशन परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

दिमाग का इस्तेमाल करें : ट्रंप की इस्राइल को सलाह, बोले- हिजबुल्ला के साथ युद्धविराम के लिए किया मजबूर

वॉशिंगटन, एजेंसी। इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच युद्धविराम की घोषणा के कुछ ही समय बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को कहा कि उन्होंने लेबनान में सक्रिय इस विद्रोही समूह के साथ संघर्ष रोकने के लिए इस्राइल से सहमति बनाने का आग्रह किया था। एनबीसी न्यूज को फोन पर दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दिन में पहले इस्राइल से संपर्क किया था और उसके नेतृत्व को युद्धविराम का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि, उन्होंने यह पुष्टि नहीं की कि क्या उन्होंने सीधे इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी। ट्रंप ने युद्धविराम को लेकर कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने इसे 'एक तरह का अतिरिक्त लाभ' बताया और पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता 60 दिनों की अवधि के लिए तकनीकी वार्ताओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ अपने संबंधों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वह हमेशा उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं। लेकिन कभी-कभी शांत रहना चाहिए और दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच नए युद्धविराम समझौते के बाद उनका यह बयान सामने आया। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और कतर की मध्यस्थता से इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच युद्धविराम पर सहमति बनी है, जो स्थानीय समय के अनुसार सुबह नौ बजे से लागू हुआ। कुछ सूत्रों ने बताया कि इस समझौते में ईरान ने भी अमेरिका और दोहा के साथ मिलकर भूमिका निभाई। हालांकि, इस्राइल रक्षा बल (आईडीएफ) के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी सेना हिजबुल्ला की ओर से उल्लंघनों के जवाब में 'तत्काल खतरों' को खत्म करना जारी रखेगी और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसी बीच, ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ होने वाली आगामी शांति वार्ता में भाग ले सकते हैं, जिसे पहले स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि स्टीव विटकॉफ अलग से शामिल होंगे। जेडी वेंस बाद में वार्ता में जुड़ सकते हैं। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को पुष्टि की कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई है, लेकिन वह बातचीत कराने के लिए तैयार है। समझौते के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौते में तुरंत और स्थायी सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही गई है। साथ ही 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया महान नेता, बोले- प्रधानमंत्री बहुत ही सख्त प्रशासक

बीजिंग, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें एक महान नेता और सख्त प्रशासक बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्सियोस के साथ एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के उन नेताओं में शामिल किया जिनकी वे सबसे ज्यादा सराहना करते हैं। इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने ताकत, कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व के मुद्दे पर बात की। इंटरव्यू के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार-बार पीएम मोदी की सराहना की। ट्रंप ने पीएम मोदी की उन खूबियों पर बात की जो उनके प्रभावशाली नेतृत्व को दर्शाती हैं। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के लंबे कार्यकाल, राजनीतिक ताकत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि की ओर इशारा किया।

ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया महान नेता

हाल ही में जी7 समिट में मिले नेताओं के बारे में बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने आमंत्रित किए गए दुनिया के तमाम नेताओं के बीच पीएम मोदी की मौजूदगी को याद किया। ट्रंप ने सरकार के प्रमुखों और देश के नेताओं की मीटिंग के बारे में बताते हुए कहा, 'भारत के प्रधानमंत्री एक महान इंसान हैं।' बाद में, जब उनसे पूछा गया कि वह एक महान नेता को कैसे परिभाषित करते हैं, तो ट्रंप ने पीएम मोदी को एक ऐसे देश में राजनीतिक स्थिरता का उदाहरण बताया, जहां पहले के नेतृत्व में बदलाव होते रहे हैं।

'प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व मजबूत'

ट्रंप ने कहा, 'मैंने जीवन भर भारत के बारे में जो देखा है, वह यही है कि लोग वहां तेजी से बदलते रहे हैं। कोई वहां छह महीने और फिर एक साल तक रहता था और फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। वे वहां 12 साल से ज्यादा समय से हैं और बहुत मजबूत हैं।' ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी शांति के साथ राजनीतिक सख्ती को भी दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, 'वह ऐसा आचरण करते हैं जैसे सब कुछ बहुत शांत है, लेकिन वह शांत स्वाभाव के इंसान नहीं हैं। वह बहुत सख्त इंसान हैं। मैं उन्हें काफी अच्छी तरह जानता हूं।'

ट्रंप बोले- पीएम मोदी की सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं

बाद में जब उनसे पूछा गया कि कौन से लोग अपनी ताकत और नेतृत्व का इस्तेमाल करने की काबिलियत के लिए सबसे अलग हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का नाम उन ग्लोबल लीडर्स में लिया जिनकी वह सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि पीएम मोदी बहुत अच्छे हैं। वे एक बेहतरीन नेता हैं। वहां 1.5 अरब लोग हैं। भारत असल में सबसे बड़ा है।' ट्रंप ने भारत के हालिया आर्थिक प्रदर्शन का जिक्र किया और अंतरराष्ट्रीय मामलों में पीएम मोदी के नजरिए को इसका क्रेडिट देते हुए कहा, 'उन्होंने कुछ बहुत अच्छे नंबर्स (आर्थिक नजरिए से) का ऐलान किया है। वह युद्ध से दूर रहते हैं, जो स्मार्ट है।'

अमेरिका-ईरान वार्ता की तैयारी तेज: स्विट्जरलैंड में परमाणु समझौते पर हो सकती है बातचीत, स्टीव विटकॉफ रवाना

वॉशिंगटन, एजेंसी। पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की नई उम्मीद दिखाई दे रही है। दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बाद अब स्विट्जरलैंड में नई वार्ता की तैयारी तेज हो गई है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना हो चुके हैं, जहां दोनों देशों के बीच संभावित परमाणु समझौते को लेकर बातचीत हो सकती है। ऐसे समय में जब क्षेत्र में सैन्य तनाव कम करने की कोशिशें चल रही हैं, यह वार्ता पश्चिम एशिया की राजनीति और वैश्विक सुरक्षा के लिए काफी अहम मानी जा रही है।

लेबनान का संघर्ष वार्ता पर इतना असर क्यों डाल रहा है?

ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि लेबनान की स्थिति उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी में हैं, लेकिन उनका दौरा क्षेत्रीय हालात पर निर्भर करेगा। मध्यस्थ देशों के सूत्रों के अनुसार अराघची ने कई देशों के विदेश मंत्रियों से कहा है कि लेबनान में संघर्ष विराम की सफलता ही अमेरिका-ईरान वार्ता के भविष्य को तय करेगी। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि जब तक संघर्ष विराम पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता, तब तक किसी बड़े कूटनीतिक कदम पर आगे बढ़ना मुश्किल होगा।

क्या स्विट्जरलैंड में शुरू होगी नई अमेरिका-ईरान वार्ता?

अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित वार्ता का पहला दौर स्विट्जरलैंड में होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर भी वार्ता से पहले स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। शुरुआत में बातचीत शुक्रवार से शुरू होनी थी, लेकिन लेबनान में इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे टाल दिया गया। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम लागू होने के बाद बातचीत का रास्ता फिर खुलता दिखाई दे रहा है। फिलहाल वार्ता की नई तारीख का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कूटनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं।

संघर्ष विराम कराने में किन देशों ने निभाई भूमिका?

लेबनान में इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच लागू हुए संघर्ष विराम के पीछे कई देशों की भूमिका बताई जा रही है। अमेरिका और कतर ने मध्यस्थ के तौर पर बातचीत को आगे बढ़ाया। वहीं कुछ कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि ईरान ने भी समझौता कराने में सहयोग किया। संघर्ष विराम स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे से लागू हुआ। क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशों के बीच इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यही समझौता आगे अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष बातचीत का आधार बन सकता है।

14 सूत्रीय समझौते में क्या-क्या शामिल है?

अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन में कई अहम बिंदु शामिल हैं। इसमें लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां रोकने और 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। समझौते के तहत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और कुछ प्रतिबंधों में ढील देने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को 60 दिनों तक सुरक्षित और निशुल्क मार्ग देने में सहयोग करेगा। इसी अवधि में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तकनीकी स्तर की बातचीत भी होगी।

प्रतिबंधों और आर्थिक सहयोग को लेकर क्या योजना है?

समझौते में ईरान पर लगे प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का खाका भी शामिल है। इसके अलावा ईरान की जमी हुई संपत्तियों को जारी करने, ईरानी तेल निर्यात के लिए अमेरिकी वित्त मंत्रालय की विशेष छूट देने और ईरान के पुनर्निर्माण व आर्थिक विकास के लिए अमेरिकी समर्थन वाले कार्यक्रम की भी बात कही गई है। इस बीच कतर ने भी अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता शुरू कराने के अपने समर्थन को दोहराया है। स्विट्जरलैंड में कतर और स्विस नेताओं के बीच हुई बैठक में क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया गया। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि स्विट्जरलैंड में होने वाली संभावित बातचीत क्या पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का रास्ता खोल पाएगी।

वोटर लिस्ट चेक करा लें, 5 योजनाओं का नहीं ले पाएंगे लाभ... सीएम डीके शिवकुमार की चेतावनी

नई दिल्ली, एजेंसी। कर्नाटक में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में सख्ती और वेरिफिकेशन को लेकर सख्ती भरा फैसला लिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही, उन्होंने ये भी कहा कि इस कदम की वजह से किसी भी हकदार लाभार्थी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

सीएम ने कहा कि 'गृह ज्योति' योजना, जिसके तहत घरों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। उसका लाभ केवल रजिस्टर्ड वोटर्स को ही मिलेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे चल रहे 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के दौरान चेक कर लें कि उनके नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। राज्य की पांच गारंटी योजनाओं में 'गृह ज्योति' शामिल है। इसके तहत घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है। 'गृह लक्ष्मी', जिसके तहत परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये मिलते हैं। 'अन्न भाग्य', जो BPL परिवारों के हर सदस्य को हर महीने 10 किलो चावल देती है। 'युवा निधि', जो 18 से 25 साल के बेरोजगार ग्रेजुएट को 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर्स को दो साल तक 1,500 रुपये देती है। और 'शक्ति', जो कर्नाटक में महिलाओं को बिना लग्जरी वाली सरकारी बसों में फ्री सफर की सुविधा देती है।

मीटिंग में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की समीक्षा की गई। इसमें ऐसे मामलों का जिक्र किया गया जिनमें 'गृह लक्ष्मी' योजना के तहत कई लाभार्थियों के लिए पेमेंट एक ही बैंक अकाउंट के ज़रिए किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग तीन लाख किस्तों के जरिए करीब 60 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

सीएम शिवकुमार ने ऐसे मामलों के बारे में भी बताया, जिनमें लाभार्थियों ने 'गृह लक्ष्मी' फंड का इस्तेमाल करके लोन चुकाने के बाद अपने बैंक अकाउंट बदल लिए थे। उन्होंने कहा, "कई लाभार्थियों ने बैंक से लोन लिया है। जैसे ही 'गृह लक्ष्मी' की रकम क्रेडिट होती है, वो लोन चुकाने में एडजस्ट हो जाती है और कुछ लोगों ने अपने अकाउंट बदल लिए हैं। ऐसे लाभार्थियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।"

मेरी हत्या की साजिश...तेज प्रताप का दावा, आकाश समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर

पटना, एजेंसी। जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष और RJD प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताया है । उन्होंने दावा किया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा सकती है और इसमें विपक्षी नेताओं की मिलीभगत हो सकती है। शुक्रवार (19 जून, 2026) की रात वो थाने पहुंचे और इस मामले में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और कहा कि इस मामले में कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की गई है। तेज प्रताप ने सचिवालय थाने में अनुष्का यादव के भाई और RJD छात्र विंग के पूर्व अध्यक्ष आकाश यादव समेत सात अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें उन पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप की अफेयर की खबरें सामने आई थीं।

राजधानी पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि चार लोग जबरन उनके घर

में घुस आए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन घुसपैठिए पकड़े जाने से पहले ही भागने में सफल रहे। उन्होंने कहा 'संभव है कि वह (आकाश यादव) विपक्ष के साथ मिलकर मेरी हत्या करवाना चाहता है। चार लोग जबरन मेरे घर में घुस आए थे। जब हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तब तक वो भाग चुके थे। मैं सुरक्षा की मांग करता हूं, और हमने सुरक्षा को लेकर अदालत में अर्जी भी दाखिल की है अगर मुख्यमंत्री से मिलना होगा, तो हम मिलेंगे'। उन्होंने दावा किया कि उनके पिता और RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव बीमार हैं और दोनों को मारने की साजिश चल रही है। तेज प्रताप ने सीधे आकाश यादव पर हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा, 'शुरू से ही मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। मेरे पिता लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं, और यह मेरे पिता और मुझे मारने की साजिश है। आकाश यादव मेरी हत्या करवाना चाहता है' JJD नेता ने सुरक्षा व्यवस्था की मांग दोहराई और संकेत दिया कि जरूरत पड़ी तो वे मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। अधिकारियों ने अभी आरोपों पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। तेज प्रताप यादव अपने वकील के साथ थाने पहुंचे थे। इस मौके पर उनके साथ उनके पीए मोतीलाल यादव भी थे।

तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी केस दर्ज

इससे पहले तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। आकाश के आवेदन पर पटना के पाटलिपुत्र थाने में FIR हुई है उसमें तेज प्रताप के साथ उनके पीए मोतीलाल यादव भी आरोपी बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि आकाश के आवेदन पर पहले थाने में केस दर्ज नहीं हुआ था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट के आदेश के बाद तेज प्रताप पर पुलिस ने FIR दर्ज की है।

शिकायत में क्या है आरोप आरोप

शिकायत में आरोप है कि उन्होंने पटना में एक घर में जबरन घुसकर एक बच्ची को अपनी बेटी बताते हुए मिलने की कोशिश की और परिवार के विरोध करने पर धमकी दी।शिकायतकर्ता का आरोप है कि तेज प्रताप और उनके एक सहयोगी ने उसके घर में घुसने की कोशिश की और बच्ची से मिलने की जिद की।यह मामला उस सोशल मीडिया विवाद के एक साल से ज्यादा समय बाद आया है जिसमें तेज प्रताप और शिकायतकर्ता के परिवार से जुड़ी एक महिला का नाम सामने आया था। हालांकि तेजप्रताप ने इन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है।

शिकायत के मुताबिक परिवार ने मिलने से मना किया तो तेज प्रताप ने बच्ची का अपहरण करवाने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री ने अपने राजनीतिक रसूख का हवाला दिया और कहा कि उनके खिलाफ कोई FIR नहीं हो सकती और परिवार को पुलिस के पास जाने से रोका।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया सामने

शिकायतकर्ता ने बताया कि बाद में उसे एक फोन आया जिसमें कॉलर ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया। पटना ASP कानून-व्यवस्था दिव्यांजलि जायसवाल ने FIR दर्ज होने की पुष्टि करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने बताया कि धमकी भरा कॉल अमेरिका के नंबर से आया था।

'द इंडिया स्टोरी' रिलीज़ से पहले फूड सेफ्टी पर काजल अग्रवाल ने अपनी दमदार पोस्ट से छेड़ी अहम बहस

देशभर में फूड एडल्टरेशन यानी खाद्य मिलावट को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच फ़िल्मि द इंडिया स्टोरी की अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने एक बार फिर इस गंभीर मुद्दे की ओर सभी का ध्यान खींचा है। हाल ही में अपनी सोशल मीडिया स्टोरी के जरिए उन्होंने भारतीय आमों के निर्यात पर कीटनाशक अवशेष और क्वारंटीन संबंधी चिंताओं को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स साझा की है। इस मुद्दे को उन्होंने अपनी आगामी फिल्म द इंडिया स्टोरी से जोड़ते हुए लिखा है, दुर्भाग्य से यह भारत की कहानी है, ये द इंडिया स्टोरी है। फिलहाल इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि फिल्म की कहानी भी खाद्य मिलावट जैसे गंभीर विषय और उसके सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरनाक प्रभावों के इर्द-गिर्द घूमती है। ज़ी स्टूडियोज़ और एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज़ के सहयोग से प्रस्तुत इस फिल्म में काजल अग्रवाल के साथ श्रेयस तलपड़े भी अहम भूमिका में नजर आनेवाले हैं। फिल्म का उद्देश्य उस सच्चाई को सामने लाना है, जो हर दिन लाखों परिवारों को प्रभावित करती है। फिल्म का निर्देशन चेतन डीके ने किया है, जबकि कहानी और निर्माण सागर बी.शिंदे ने संभाली है। द इंडिया स्टोरी 24 जुलाई 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में रिलीज़ होगी। सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषय और प्रभावशाली संदेश के साथ यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि एक जरूरी राष्ट्रीय चर्चा की शुरुआत करने का लक्ष्य रखती है।

फिल्म के सह-निर्माताओं में स्वाति विनायक सैदाने, अनिता जाधव, विनायक सैदाने, कल्पेश शाह, देवयानी खोराते और प्रेम जोशी शामिल हैं। वहीं तकनीकी टीम में सिनेमैटोग्राफर निशांत भागवत, संगीतकार मंगेश धाकड़े, एडिटर आशीष म्हात्रे, गीतकार शकील आज़मी और साउंड डिज़ाइनर अनमोल भावे शामिल हैं।

वेलकम टू द जंगल से धमाकेदार गाना दीवाने हैं जारी , 22 साल बाद साथ झूमे अक्षय और रवीना

अक्षय कुमार स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल अब बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। वेलकम फ्रेंचाइजी की इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही उस्ताह बना हुआ था। हाल ही में रिलीज ट्रेलर के बाद से लोगों की बेचैनी फिल्म को लेकर और बढ़ गई है। अब फिल्म रिलीज से 8 दिन पहले मेकर्स ने इसका एक और धमाकेदार ट्रैक दीवाने हैं रिलीज कर दिया गया है, जिसमें तमाम सितारों के बीच रवीना और अक्षय की जोड़ी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है।

बता दें कि ये गाना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और आनंद राज आनंद ने गाया है। माना जा रहा है कि ये गाना दर्शकों दर्शकों के दिलों में बसी पुरानी यादों को फिर से तरोताजा कर देगा। कश्मीरी लोक गीत रक्षिदा रक्षिदा के शानदार मेल से सजे इस जोशीले गाने में अक्षय कुमार के साथ रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस की जोड़ी दिख रही है।

इस गाने पर लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। एक ने कहा है- ये तो पता नहीं लेकिन घिस घिस गाना थिएटर में धूम मचाएगा। एक यूजर ने कहा- अब रीमेक गाने का रोना बंद होना चाहिए, क्या जबरदस्त ओरिजिनल गाना है। एक और ने कहा- ये चार्टबस्टर गाना है। एक अन्य यूजर ने कहा- इस गाने को केवल अक्की और रवीना पर फिल्माना चाहिए था। एक यूजर ने कहा- 90 के दशक की फीलिंग आ रही है इस गाने में सभी किरदार बेहतरीन हैं। एक अन्य फैन ने कहा- बहुत समय बाद हम असली गाना सुन रहे हैं, आनंद राज आनंद ने कमाल कर दिया। एक और यूजर ने कहा- आनंद राज आनंद ने हमें 90 के दशक और 2000 के दशक में अनगिनत यादें दीं, बॉलीवुड के सबसे कम आंके जाने वाले हिटमेकर की आखिरकार वापसी हो गई है, इस गाने और इस वापसी को वह सारी सफलता मिले जिसके वे हकदार हैं।

इस गाने में रवीना के साथ अक्षय कुमार की केमिस्ट्री सभी को गुदगुदा रही है। ये गाना हर तरह से लोगों को नोस्टैलजिक फील दे रहा है। लोगों ने कहा है- एक बार फिर इनके रोमांस के वो पुराने किस्से दिमाग में घूमने लगे।

वहीं फिल्म में इस फिल्म में बड़ी स्टारकास्ट शामिल है, जिसमें अक्षय और रवीना के अलावा जैकलीन, दिशा पाटनी, सुनील शेट्टी,अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, विंदू दारा सिंह, उर्वशी रौतेला जैसे मंझे हुए कलाकारों ने फिल्म में खास भूमिका निभाई है।

बताते चलें कि फिल्म वेलकम टू द जंगल का निर्देशन अहमद खान ने किया है। यह फिल्म वेलकम फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग है। इसमें अक्षय कुमार लीड रोल में में हैं, जो अपने आइकॉनिक अंदाज में वापसी कर रहे हैं। साजिद नाडियाडवाला और स्टार स्टूडियोज द्वारा निर्मित फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'आर्ट बिना पॉलिटिक्स के अधूरा', सेलेब्रिटीज के राजनीतिक मुद्दों पर बोलने पर क्या बोले अली फजल? साझा की राय

एक्टर अली फजल इन दिनों वेब सीरीज 'राख' में नजर आ रहे हैं। अब हाल ही में उन्होंने इस बात पर अपनी राय रखी कि क्या सेलेब्रिटीज को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बोलना चाहिए या नहीं।

अली फजल इन दिनों राख वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं। इस सीरीज को लोगों से काफी सराहना मिल रही है। इस बीच अली ने बड़े अहम मुद्दे पर अपनी राय दी है।

एक बातचीत के दौरान अली से पूछा गया कि क्या पब्लिक फिगर्स को इन मुद्दों पर अपनी राय देनी चाहिए। इस पर अली ने कहा कि उनके हिसाब से आर्ट बिना पॉलिटिक्स के अधूरा है। उनका मानना है कि कलाकारों को अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब हमेशा जोर-जोर से बोलना या मंच पर खड़े होकर भाषण देना नहीं होता। अपनी बात रखने के कई तरीके हो सकते हैं।

आर्ट और पॉलिटिक्स एक-दूसरे से जुड़े होते हैं

अली फजल ने आगे कहा कि कलाकारों के अंदर एक संवेदनशीलता होती है और वे अपने आसपास के समाज से खुद को पूरी तरह अलग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आर्ट और पॉलिटिक्स अक्सर एक-दूसरे से जुड़े होते हैं।

'एक कलाकार के तौर पर हममें बहुत करुणा होती है। लेकिन आर्ट उस समाज और पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकता, जिसमें हम रहते हैं। कई बार आर्ट उसी का आईना होता है और कई बार उसी से प्रेरित होता है। इसे अलग नहीं किया जा सकता।'

जरूरी नहीं कि मंच पर खड़े होकर चिल्लाया जाए

उन्होंने यह भी माना कि आज के समय में कई लोग इन मुद्दों पर बोलना नहीं चाहते, और यह भी ठीक है क्योंकि हर किसी की अपनी परिस्थितियां होती हैं। लेकिन उनका मानना है कि हमें अपने-अपने तरीके से कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए।

अली ने यह भी साफ किया कि अपनी बात रखना हमेशा बड़े-बड़े भाषण देने जैसा नहीं होता। उन्होंने कहा, 'हर किसी का अपना तरीका होता है। जरूरी नहीं कि मंच पर खड़े होकर चिल्लाया जाए। कई बार अच्छी कहानियां लिखकर, उन्हें पर्दे पर दिखाकर भी बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। कभी-कभी वही सबसे जोरदार आवाज बनती है।'

12 जून को रिलीज हो चुकी है 'राख'

वेब सीरीज 'राख' का निर्देशन 'परी' और 'पाताल लोक' जैसी डार्क दुनिया रच चुके प्रोसित रॉय ने किया है। यह 12 जून से अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है। इसमें अली फजल और सोनाली बेंद्रे अहम भूमिका में हैं।

वहीं आकाश मखीजा, रमनदीप यादव, दिव्या शर्मा और विवान शर्मा भी वेब सीरीज में खास भूमिका निभाते हैं। वेब सीरीज 'राख' रिलीज हो चुकी है। यह सीरीज 1978 के कुख्यात रंगा-बिल्ला केस से प्रेरित है, जिसे भारत के सबसे खौफनाक अपराधों में गिना जाता है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित ।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com